छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg No-CHHHIN/2020/87351

डाक पंजीयन क्र. 046/Surguja Dn/2024-26

www.cgfrontline.com

वर्ष - 06 अंक - 274 बैकुंठपुर, शनिवार 08 अगस्त 2026 पृष्ठ -8 मूल्य -1

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में लक्ष्य हासिल करने वाला एमसीबी बना छत्तीसगढ़ का पहला जिला

एमसीबी ने 95-95-95 राष्ट्रीय लक्ष्य में दर्ज की ऐतिहासिक उपलब्धि

छ.ग.फ्रंटलाइन

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)। एमसीबी जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी के मार्गदर्शन एवं प्रभावी नेतृत्व में एमसीबी जिले ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एचआईवी नियंत्रण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 95-95-95 राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। इस उपलब्धि के साथ एमसीबी छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन गया है, जिसने इस चुनौतीपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल कर राज्य का गौरव बढ़ाया है।

इस उपलब्धि के पीछे सुनियोजित रणनीति, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, समयबद्ध उपचार और स्वास्थ्य विभाग की समर्पित टीम का सतत प्रयास रहा। जिले में एचआईवी कार्यक्रम का प्रभावी संचालन जिला नोडल अधिकारी डॉ. मो. वसीक अस्दक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक शिशिर जायसवाल के कुशल निर्देशन में किया गया, जिनके नेतृत्व में मैदानी स्तर पर अभियान को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। एचआईवी संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95-95-95 लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एमसीबी जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। संभावित एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की समय पर पहचान एवं जांच कर जिले ने पहला 95 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। संक्रमित पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ऋक्ष) से जोड़कर दूसरा 95 प्रतिशत लक्ष्य भी सफलतापूर्वक हासिल किया। संक्रमित मरीजों के शरीर में वायरस की सक्रियता को न्यूनतम स्तर पर लाने के 99 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले जिले ने 98 प्रतिशत वायरल लोड सप्रेशन प्राप्त कर असाधारण प्रदर्शन किया, जो राष्ट्रीय मानकों के अत्यंत निकट है। इस सफलता में इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर के काउंसलरों का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा। श्रीमती निशा सिंह एवं विजेंद्र खटकर ने मरीजों की प्रभावी काउंसलिंग, नियमित फॉलोअप तथा उपचार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समर्पण और संवेदनशील कार्यशैली ने मरीजों का विश्वास बढ़ाने के साथ-साथ कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को जाता है। दिशा टीम, आईसीटीसी, एआरटी केंद्र, विशेषज्ञ चिकित्सकों, लैब तकनीशियनों तथा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों ने समन्वित रूप से कार्य करते हुए कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सभी के सामूहिक प्रयास, समर्पण और सेवा भावना ने एमसीबी जिले को यह विशिष्ट पहचान दिलाई। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एवं जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों, चिकित्सकों, काउंसलरों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की है। जिला प्रशासन ने यह भी संकल्प दोहराया है कि भविष्य में भी जिले में एचआईवी की प्रभावी रोकथाम, शत-प्रतिशत समय पर जांच, समय पर उपचार एवं दवाओं की उपलब्धता तथा मरीजों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर सुनिश्चित की जाएंगी। एमसीबी की यह सफलता केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि समर्पित नेतृत्व, प्रभावी टीम वर्क और जनस्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रेरक उदाहरण है। यह उपलब्धि आने वाले समय में पूरे प्रदेश के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

* **अम्बिकापुर।** जिले की समस्त 439 ग्राम पंचायतों में चावल महोत्सव के साथ रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का व्यापक आयोजन किया गया। ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों का ग्राम पंचायत स्तर पर निराकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।

शासकीय कर्मचारी द्वारा राजनीतिक एवं आपत्तिजनक पोस्ट साझा करना सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन, निष्पक्ष जांच हो: अशोक श्रीवास्तव

■ सरकारी कर्मचारी की राजनीतिक पोस्टिंग पर कांग्रेस सख्त, कलेक्टर से की अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग

छ.ग.फ्रंटलाइन

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)। जिला कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायत लालपुर में पदस्थ पंचायत सचिव भुवनेश्वर सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर राजनीतिक एवं विवादित पोस्ट साझा किए जाने के मामले में जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि एक शासकीय कर्मचारी का दायित्व निष्पक्ष एवं सेवा आचरण नियमों के अनुरूप कार्य करना है। यदि कोई शासकीय सेवक सार्वजनिक सोशल मीडिया या व्हाट्सएप समूहों में राजनीतिक एवं विवादित सामग्री साझा करता है, तो इससे उसकी निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है तथा शासन-प्रशासन की गरिमा भी प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि शिकायत के साथ प्रस्तुत स्क्रीनशॉट में ग्राम पंचायत लालपुर के पंचायत सचिव द्वारा एक व्हाट्सएप समूह में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से संबंधित राजनीतिक एवं विवादित पोस्ट अग्रेषित (फॉरवर्ड) किए जाने का उल्लेख है। ऐसे कृत्य प्रथम दृष्टया शासकीय सेवा आचरण नियमों के विपरीत प्रतीत होते हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कलेक्टर से मांग की है कि पंचायत सचिव द्वारा साझा की गई पोस्ट की तथ्यात्मक जांच कराई जाए, उनके विरुद्ध शासकीय सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन की विभागीय जांच की जाए तथा आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को भी आवश्यक जांच एवं कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित की गई है। अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आवश्यकता है। किसी भी शासकीय कर्मचारी द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता अथवा पक्षपातपूर्ण सामग्री का प्रचार-प्रसार जनविश्वास को प्रभावित करता है, इसलिए इस मामले में निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

शासकीय पॉलीटेक्निक चिरमिरी में अंशकालीन व्याख्याताओं की भर्ती

एमसीबी। शासकीय पॉलीटेक्निक चिरमिरी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंशकालीन (पार्ट-टाइम) व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। संस्थान में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने तथा रिक्त विषयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। प्राचार्य कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार 12 अगस्त 2026 को प्रातः 11:00 बजे शासकीय पॉलीटेक्निक चिरमिरी परिसर में साक्षात्कार आयोजित होगा। भर्ती सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग एवं जियोलॉजी विषयों के लिए की जाएगी, जिसमें प्रत्येक विषय के लिए एक-एक अंशकालीन व्याख्याता का चयन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने समस्त मूल शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्वप्रमाणित प्रतियां लेकर उपस्थित होना होगा। प्रत्येक विषय के लिए अभ्यर्थियों के पास अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है।

संस्थान ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूर्णतः वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से संपन्न होगी। चयनित अभ्यर्थियों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा संस्थान की आवश्यकता एवं शासन के निर्देशों के अनुसार प्रभावी रहेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता (टीए/डीए) देय नहीं होगा तथा चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

कोरिया वन मंडल के रेगुलर रेंज सोनहत के प्लांट टेशन में बेशकीमती वृक्ष सागौन की अंधाधुंध कटाई जोरों पर

छ.ग.फ्रंटलाइन

सोनहत। कोरिया वन मंडल परिक्षेत्र सोनहत के प्लांट टेशन जंगलों में बेशकीमती वृक्ष सागौन की कटाई रेन्जर के कार्य प्रणाली के उदासीनता के कारण अनवरत जारी है रेन्जर वन पाल को अपना पर्सनल काम करवाने में लेते हैं जिससे वन पाल भी रेन्जर से छुट्टी मिलता है तो बकायदा ऐ सी रूम में अपना आराम फरमाते हैं चाहे जंगल कुछ भी हो इन दोनों को कोई मतलब नहीं है चाहे कोई अतिक्रमण करे चाहे पुरी जंगल काट के ले जाये मासिक वेतन महीना पुरते ही दन से खाता में फुल मेपेटं आ ही जाता है सोनहत बेलिया के जंगलों में क ई साल पहले सागौन प्लांट तैयार किया गया था जो अब विशालकाय वृक्ष बन चुके हैं उन वृक्षों को रेन्जर से सांठगांठ करके अंधाधुंध कटाई कि जा रही है इन बरसात के दिनों में न कभी रेन्जर जाते हैं न तो वन रक्षक भगवान भरोसे जंगल चल रही है जंगलों के रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं इस कारण जैव विविधता संपदा पर विपरीत असर पड़ रहा है जंगलों के जीव जंतु जानवरों के लिए सरकार तालाब निर्माण चेक डेम स्टाप डेम इत्यादि जल सोत्रो को संजोने का काम कर रही है लेकिन फील्ड के अधिकारी पुरी तरह से धरातल पर फीसडी साबित हो रहे हैं जमीनी हकीकत जीरों है अगर वन विभाग की निर्माण कार्य की जांच स्वंतत्र एजेंसी से कराई जाये तो सभी निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं जंगल के जीव जंतु सिर्फ प्रकृति से निर्मित जलाशयों से अपनी प्यास बुझा रहे हैं हर साल करोड़ों की विकास कार्य सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित है इन निर्माण कार्य में वन पाल रेन्जर एवं उच्च अधिकारी माला माल हो जाते हैं वन विभाग के अधिकारियों की तो बात ही अलग हैं वन रक्षक साल भर के अंदर चमचमाती मंहगी कार में नजर आने लगते हैं ये कोन सा कुबेर का खजाना पा जाते है न तो ये किसी बैंक से लोन लेते हैं न कर्ज लेकिन फिर भी मंहगी कार की सवारी इनकी शान शौकत है।

ग्राम पंचायतों में रोजगार सह आवास दिवस आयोजित

कलेक्टर रोक्तिमा यादव के निर्देश पर रोजगार

■ आवास और जल संरक्षण पर विशेष अभियान

छ.ग.फ्रंटलाइन

बैकुंठपुर। कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देशानुसार जिले की ग्राम पंचायतों एवं कार्यस्थलों पर रोजगार सह आवास दिवस मनाया गया। बारिश के बीच चावल महोत्सव के साथ आयोजित कार्यक्रम में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं विकसित भारत जीरामजी अभियान के कार्यों की समीक्षा की गई। श्रमिकों की मांग, शिकायतों और लंबित मामलों के निराकरण पर भी पहल की गई।

पंजीकृत श्रमिकों के लंबित भुगतान की जानकारी दी गई। विकसित भारत जीरामजी के तहत जल संरक्षण, भूजल संवर्धन, बालिका शौचालय एवं मुक्तिधाम शेड से जुड़े कार्यों की जानकारी देकर ग्रामीणों की मांग एवं सुझाव लिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित निर्माण कार्यों की समीक्षा कर हितग्राहियों को शीघ्र निर्माण पूरा करने के लिए प्रेरित किया गया। जियो टैगिंग और स्वीकृत आवासों को समय पर पूर्ण कराने की कार्ययोजना भी बनाई गई। आजीविका डबरियों में मत्स्य पालन और प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी महिला स्व-सहायता समूहों को दी गई, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। ग्रामीणों को वर्षा जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के महत्व की जानकारी दी गई। मनरेगा के प्रगतिरत कार्य शीघ्र पूरे करने तथा मांग आधारित नए कार्य शुरू करने पर भी चर्चा हुई। 'मेरी बेटी, मेरा अभिमान' अभियान के तहत बालिका शौचालय निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने तथा ग्रामसभा के प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता वाले कार्य दिसंबर 2026 तक पूरे करने की रूपरेखा बनाई गई। साथ ही सभी कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूर्ण कराने का संकल्प लिया गया।

क्रीड़ा परिसर लालपुर में लायंस क्लब और ग्रीन वैली क्लब ने किया वृहद वृक्षारोपण

छ.ग.फ्रंटलाइन

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)। पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने और प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनेन्द्रगढ़ के लालपुर स्थित क्रीड़ा परिसर में लायंस क्लब मनेन्द्रगढ़ एवं ग्रीन वैली क्लब के संयुक्त तत्वावधान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रेरणादायी आयोजन में क्रीड़ा परिसर के खिलाड़ियों, छात्र-छात्राओं, प्रशिक्षकों तथा क्लब के पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

कार्यक्रम के दौरान क्रीड़ा परिसर के खेल मैदान एवं आसपास के क्षेत्र में फलदार, छायादार तथा औषधीय पौधों का रोपण किया गया। छात्र-छात्राओं ने अपनी माताओं के सम्मान में पौधे लगाकर उन्हें प्रकृति से जोड़ने का भावनात्मक संदेश दिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधारोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण और नियमित देखभाल का भी संकल्प लिया।

इस अवसर पर लायंस क्लब एवं ग्रीन वैली क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मातृत्व के सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संदेश देने वाला अभियान है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो धरती को पुनः हरा भरा बनाया जा सकता है। ग्रीन वैली क्लब के कौशल अग्रवाल ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वृक्ष पृथ्वी के जीवन का आधार हैं। उन्होंने सभी से अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। विनोद जायसवाल ने कहा कि पौधारोपण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और नियमित देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को अधिक से अधिक लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करना चाहिए, तभी इस अभियान का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। रामचरित द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि वृक्ष हमें जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और गर्मी के दिनों में शीतल छाया देकर जीवन को सहज बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रकृति हमारे बिना तो जीवित रह सकती है, लेकिन प्रकृति के बिना मानव जीवन एक दिन भी संभव नहीं है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण हम सभी का नैतिक दायित्व है। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, अधिकारियों एवं क्लब सदस्यों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई। क्रीड़ा परिसर के अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों ने लायंस क्लब और ग्रीन वैली क्लब के इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी पहल बताया। इस अवसर पर लायंस क्लब मनेन्द्रगढ़, ग्रीन वैली क्लब के पदाधिकारी, क्रीड़ा परिसर के अधिकारी-कर्मचारी, प्रशिक्षक तथा बड़ी संख्या में खेल प्रतिभागी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

स्वतंत्रता दिवस पर जिले की सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद

बैकुंठपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रोक्तिमा यादव ने आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के निर्देशों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त 2026 (शनिवार) को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार 15 अगस्त 2026 को जिला कोरिया की सभी देशी, विदेशी, कम्पोजिट एवं प्रीमियम मदिरा की फुटकर दुकानें, एफ.एल.-3 (ग) (पर्यटन बार), एफ. एल.-4 (क) (व्यावसायिक क्लब) आहाता पूर्णतः बंद रहेंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों/ संचालकों को निर्देशित किया है।

अवैध शराब पर आबकारी का शिकंजा, महुआ शराब व एमपी की अंग्रेजी शराब जब्त

छ.ग.फ्रंटलाइन

बैकुंठपुर। कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाते हुए दो अलग-अलग कार्रवाई में 12 लीटर महुआ शराब और 4.140 लीटर मध्यप्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की है। ग्राम तोलगा में छापेमारी के दौरान सुशील लकड़ा के कब्जे से 12 लीटर महुआ शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में राजेंद्र कुमार के कब्जे से 23 पाव (4.140 लीटर) मध्यप्रदेश निर्मित गोवा व्हिस्की जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई। जिला आबकारी अधिकारी रमेश अग्रवाल के निर्देशन में हुई कार्रवाई में आबकारी टीम की सक्रिय भूमिका रही। विभाग ने आमजन से अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन की सूचना तत्काल देने की अपील की है।

ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री हलाकान, मालगाड़ियों को प्राथमिकता देने से बढ़ी परेशानी

अंबिकापुर-बौरीडांड रेलखंड पर रोज घंटों लेट चल रही यात्री ट्रेनें, डबल लाइन बनने तक राहत के आसार नहीं

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंबिकापुरङ्कबौरीडांड रेलखंड पर यात्री ट्रेनों की लगातार चल रही लेटलतीफी अब आम यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। इस रेलखंड पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों को प्रतिदिन घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाने से नौकरीपेशा लोग, विद्यार्थी, मरीज, व्यापारी और अन्य यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि इस मार्ग पर रेल के अलावा कोई सुलभ और सुविधाजनक विकल्प नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी में घंटों विलंब से चलने वाली ट्रेनों का इंतजार करना पड़ता है।

यात्रियों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेलवे प्रबंधन यात्री ट्रेनों की अपेक्षा मालगाड़ियों के संचालन को अधिक प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि अंबिकापुरङ्कबौरीडांड रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों पर यात्री ट्रेनों को लंबे समय तक रोककर पहले मालगाड़ियों को पास कराया जाता है। कई बार ट्रेनें 30 मिनट या उससे अधिक समय तक स्टेशनों पर खड़ी रहती हैं। इससे यात्रा न केवल लंबी और थकाऊ हो जाती है, बल्कि यात्रियों में रेलवे व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी बढ़ रही है।

रेलवे के जानकारों का कहना है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे देश के सबसे अधिक माल लदान करने वाले जोन में शामिल है। कोयला परिवहन से रेलवे को बड़ी आय होती है, इसलिए मालगाड़ियों का परिचालन

प्राथमिकता से कराया जाता है। हालांकि इसका सीधा असर यात्री ट्रेनों के समय पर पड़ रहा है और आम यात्रियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।

सिंगल लाइन पर बढ़ा ट्रैफिक

अंबिकापुर से बौरीडांड तक अभी भी सिंगल रेल लाइन है। इसी एक लाइन से यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों संचालित होती हैं। पहले इस रेलखंड पर ट्रेनों का दबाव अपेक्षाकृत कम था, लेकिन अदानी की परसा-केते और हसदेव क्षेत्र की कोयला खदानों के विस्तार के बाद मालगाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बताया जाता है कि परसा-केते खदान से प्रतिदिन लगभग 12 से 15 रैक कोयले का डिस्पैच किया जाता है। इसके अलावा बिश्रामपुर, भटगांव, बैकुंठपुर और चर्चा क्षेत्र की खदानों से भी रोजाना बड़ी संख्या में कोयला रैक रवाना होते हैं। वहीं बिश्रामपुर गुड्स शेड में सीमेंट, उर्वरक, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की रैक भी नियमित रूप से पहुंचती हैं। ऐसे में एक ही लाइन पर बढ़ते रेल यातायात का सीधा असर यात्री ट्रेनों की समयपालन व्यवस्था पर पड़ रहा है।

मेमू ट्रेन की लेटलतीफी बनी सबसे बड़ी समस्या

शहडोलङ्कअंबिकापुर तथा अंबिकापुरङ्कअनूपपुर के बीच संचालित मेमू ट्रेन शुरुआत से ही लगातार विलंब से चल रही है। यह ट्रेन रोजाना यात्रा करने वाले कर्मचारियों,स्थानीय लोगो और छोटे व्यापारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसके घंटों लेट होने से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो रही है।

कई यात्रियों की बिलासपुर, अनूपपुर, कटनी और अन्य स्थानों के लिए कनेक्टिंग ट्रेनें छूट जाती हैं, जिससे उन्हें घंटों स्टेशन पर इंतजार करना पड़ता है या फिर वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ता है। यात्रियों का कहना है कि यदि ट्रेन को समय पर संचालित नहीं किया जा सकता तो रेलवे को समय-सारिणी में सुधार करना चाहिए, ताकि यात्रियों को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।

डबल लाइन परियोजना से जगी उम्मीद

लगातार बढ़ते रेल यातायात और यात्रियों की शिकायतों को देखते हुए रेलवे ने इस रेलखंड के दोहरीकरण की स्वीकृति दी है। पहले चरण में सूरजपुर से बैकुंठपुर तक लगभग 46 किलोमीटर तथा दूसरे चरण में बैकुंठपुर से बौरीडांड तक लगभग 42 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण किया जा रहा है। निर्माण कार्य कई स्थानों पर तेजी से जारी है।

रेलवे सूत्रों के अनुसार परियोजना पूरी होने के बाद मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों का संचालन अलग-अलग ट्रैक पर अधिक सुचारु रूप से हो सकेगा। इससे ट्रेनों के क्रॉसिंग में लगने वाला समय कम होगा और यात्री ट्रेनों की लेटलतीफी में काफी हद तक सुधार आने की उम्मीद है। हालांकि परियोजना पूरी होने तक यात्रियों को वर्तमान स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

यात्रियों की मांग

स्थानीय यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि दोहरीकरण कार्य पूरा होने तक यात्री ट्रेनों के संचालन में बेहतर समन्वय किया जाए। जहां संभव हो, अनावश्यक ठहराव कम किए जाएं और मालगाड़ियों के साथ संतुलन बनाकर यात्री ट्रेनों को भी समय पर चलाने का प्रयास किया जाए। उनका कहना है कि रेलवे की आय बढ़ाने के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा और समय की भी समान रूप से चिंता की जानी चाहिए।

जयनगर खाद घोटाले में मार्कफेड बिश्रामपुर के गोदाम प्रभारी निलंबित, जांच गोदाम तक पहुंची

कॉपरेटिव बैंक के पूर्व मैनेजरों को भी सीईओ द्वारा नोटिस जारी करने की जानकारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। जयनगर सहकारी समिति में सामने आए खाद घोटाले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जयनगर समिति प्रबंधक श्यामलाल प्रजापति के निलंबन और समिति अध्यक्ष देवधन राम बिंझिया से बोर्ड की शक्तियां वापस लेने के बाद अब कार्रवाई की आंच छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के डबल लॉक खाद गोदाम बिश्रामपुर तक पहुंच गई है।जिला सहकारी विपणन संघ गोदाम के प्रभारी एवं क्षेत्र सहायक लिवेन खेस्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मार्कफेड मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा 27 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, डबल लॉक खाद गोदाम में रासायनिक उर्वरकों के भौतिक सत्यापन के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। जांच में खाद के भंडारण और वितरण में गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर सेवा नियम, 2007 के तहत यह कार्रवाई की गई।

आदेश के मुताबिक, भौतिक सत्यापन में वास्तविक खाद का स्टॉक ऑनलाइन दर्ज मात्रा से काफी कम मिला। इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता मानते हुए गोदाम प्रभारी को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय जशपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

बता दें कि जयनगर समिति प्रबंधक द्वारा खरीफ वर्ष में किसानों को खाद उपलब्ध न करा उन्हें रोज समिति का चक्कर लगवाया जा रहा था जिसकी शिकायत किसानों ने कलेक्टर से की ।कलेक्टर के निर्देश पर पखवाड़े भर पूर्व समिति की जांच कराई गई जिसमें करीब चालीस लाख से ऊपर का उर्वरक भौतिक सत्यापन में शॉर्ट मिला जिसके बाद समिति प्रबंधक को निलंबित कर अध्यक्ष से बोर्ड की शक्तियां वापस ले ली गई ।बताया गया कि पूर्व के वर्षों खरीफ और रवि सीजन में भी प्रबंधक द्वारा भारी गड़बड़ी की गई है उक्त बाते भी जांच में सामने आई है जिसके बाद कॉपरेटिव बैंक के सीईओ ने बिश्रामपुर बैंक के पूर्व प्रबंधकों को मामले की अनदेखी करने मिलीभगत की आशंका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगे जाने की खबर है।

बालक विद्यालय के 51 छात्रों का एनसीसी हेतु हुआ चयन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एनसीसी के नए कैडेट्स चयन हेतु भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया। भर्ती अभियान का आयोजन 01 सीजी एनसीसी बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल सैन्थिल कुमार एस एवं एडमिन अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमित यादव के निर्देशन तथा 1 सीजी बटालियन, कोरबा के तकनीकी मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। भर्ती अभियान में विद्यालय के 82 विद्यार्थियों ने उत्साह एवं राष्ट्रसेवा की भावना के साथ भाग लिया। चयन प्रक्रिया के संचालन में विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुजूर तथा भारतीय सेना के जेसीओ महेन्द्र शर्मा का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन रहा। वहीं विद्यालय के एनसीसी अधिकारी फर्स्ट ऑफिसर सुनील दत्त तिवारी एवं स्काउट-गाइड अधिकारी ओम प्रकाश राजवाड़े के सहयोग से संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी एवं अनुशासित ढंग से संपन्न हुई। भर्ती प्रक्रिया भारतीय सेना के निर्धारित मानकों के अनुरूप

विभिन्न चरणों में आयोजित की गई। प्रारंभिक चरण में प्रतिभागियों की ऊंचाई एवं अन्य शारीरिक मापदंडों का परीक्षण किया गया, जिसका संचालन विक्की विश्वकर्मा एवं कुलदीप सिंह ने किया। इसके पश्चात अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच के लिए सौ व दो सौ मीटर दौड़, पुश-अप, सिट-अप सहित अन्य परीक्षण आयोजित किए गए। साथ ही अभ्यर्थियों की बौद्धिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई। सभी निर्धारित मापदंडों एवं परीक्षणों में सफल प्रदर्शन करने वाले 51 विद्यार्थियों का दो वर्षीय एनसीसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए चयन किया गया।

पेयजल संकट हुआ दूर, नहालुकोना पारा के परिवारों को मिली त्वरित राहत

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। हर शिकायत का त्वरित समाधान' मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इसी सोच को साकार कर रही है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आज केवल शिकायत दर्ज कराने का माध्यम नहीं, बल्कि आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसेमंद मंच बन चुकी है। जहां दर्ज हर शिकायत पर संवेदनशीलता और समयबद्धता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कुसमी विकासखंड के नहालुकोना पारा में पांच माह से बंद पड़े हैंडपंप का कुछ ही समय में सुधार इसका जीवंत उदाहरण है। कभी-कभी एक छोटी-सी शिकायत भी कई परिवारों की बड़ी परेशानी दूर कर देती है। विकासखंड कुसमी के ग्राम पंचायत चटनियां के नहालुकोना पारा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले पांच महीनों से खराब पड़े हैंडपंप के कारण लोगों को हर दिन पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को होती थी। सुबह की शुरुआत पानी की तलाश से होती और दिनभर पेयजल की चिंता बनी रहती थी। इस समस्या से परेशान होकर

ग्रामीण सूर्यकांत यादव ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग टीम मौके पर पहुंच हैंडपंप की तकनीकी खराबी दूर की। हैंडपंप से दोबारा पानी निकलते ही नहालुकोना पारा में अब लोगों को पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। घर के पास ही स्वच्छ पानी मिलने से ग्रामीणों की दिनचर्या आसान हो गई है।

ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें भरोसा नहीं था कि इतनी शीघ्रता से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत का समाधान हो जाएगा। समस्या के त्वरित समाधान से शासन और प्रशासन के प्रति आमजनों का भरोसा और मजबूत हुआ है।

गौरतलब है कि कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए हैं।

अरुणोदय के 19 विद्यार्थियों ने सीजी पीएससी, एसआई प्रारंभिक परीक्षा में पाई सफलता

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डीएमएफ मद से संचालित अरुणोदय करियर इंस्टीट्यूट से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उप निरीक्षक के प्रारंभिक परीक्षा में 19 छात्रों ने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया है।

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अरुणोदय करियर इंस्टीट्यूट लगातार बेहतर कार्य कर रहा है। जिला प्रशासन द्वारा स्थापित यह इंस्टीट्यूट जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों से आने वाले प्रतिभाओं को नया आयाम देने में सार्थक सिद्ध हो रहा है। हाल ही में आयोग द्वारा जारी उप निरीक्षक के प्रारंभिक परिणाम में अरुणोदय कैरियर इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता साबित की है।

कलेक्टर ने मुख्य परीक्षा के लिए चयनित सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। और कहा कि आपकी मेहनत और लगन ने यह मुकाम दिलाया है। उपलब्धि अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बनें। धैर्य, निरंतरता एवं ईमानदारी से परिश्रम करने की सलाह भी दी। कलेक्टर के निर्देश, जिला खनिज संस्थान न्यास फंड के वित्तीय सहयोग एवं आदिवासी विकास विभाग के नेतृत्व में यह संस्था संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य जिले के सुदूर एवं प्रतिभावान युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त व गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराना है। ग्रामीण, आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को बिना किसी वित्तीय बोझ के उच्चस्तरीय मार्गदर्शन देने वाला यह संस्थान लगातार बेहतर परिणाम दे रहा है। अरुणोदय करियर इंस्टीट्यूट से अब तक सौ से अधिक अभ्यर्थी शासकीय सेवाओं में चयन प्राप्त कर चुके हैं, जबकि विभिन्न परीक्षाओं में 2 सौ से अधिक छात्र-छात्राओं ने सफलता का परचम लहराया है। ताज़ा नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि यदि सही मार्गदर्शन, प्रशासनिक सहयोग और अनुशासित अध्ययन का संगम हो, तो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है।

संस्था के शिक्षकों ने जानकारी दी कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल सभी 19 अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा की विशेष गहन तैयारी एवं टेस्ट सीरीज तत्काल प्रभाव से प्रारंभ की जा रही है।

आयुष्मान कार्ड महाअभियान में संकल्प, रणनीति और सतत मॉनिटरिंग से मिली गति

विशेष महाअभियान के पहले एवं दूसरे दिवस प्रदेश में रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं को हर पात्र परिवार तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन का संकल्प अब उपलब्धियों में बदलता नजर आ रहा है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के नेतृत्व में संचालित विशेष आयुष्मान एवं वय वंदन कार्ड महाअभियान में संकल्प, रणनीति एवं सतत् मॉनिटरिंग से अभियान को गति मिल रही है।

जिले में 05 से 07 अगस्त 2026 तक विशेष आयुष्मान एवं वय वंदन कार्ड महाअभियान संचालित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों से लेकर नगरीय निकायों तक विशेष शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड तथा 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के वय वंदन कार्ड बनाए जा रहे हैं।

महाअभियान के पहले ही दिन जिले ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक आयुष्मान एवं वय वंदन कार्ड बनाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि जिला प्रशासन की सुनियोजित रणनीति, सतत मॉनिटरिंग, विभागीय समन्वय और मैदानी अमले की अथक

मेहनत का परिणाम है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी स्वयं अभियान की नियमित समीक्षा कर रही हैं तथा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे।

महाअभियान के पहले दो दिनों में जिले में 4350 आयुष्मान कार्ड एवं 331 वय वंदन कार्ड बनाकर कुल 4681 कार्ड बनाए गए, जो कि जिले की उपलब्धि है। जहां जिले के सभी छह विकासखंडों में बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने शिविरों में पहुंचकर अपना पंजीयन कराया।

महाअभियान के दौरान जिले के सभी छह विकासखंडों में व्यापक स्तर पर शिविर आयोजित किया गया। विकासखंड बलरामपुर में 1215 आयुष्मान कार्ड एवं 67 वय वंदन कार्ड, रामचंद्रपुर में 561 आयुष्मान कार्ड एवं 36 वय वंदन कार्ड, वाड्रफनगर में 1277 आयुष्मान कार्ड एवं 59 वय वंदन कार्ड, राजपुर में 385 आयुष्मान कार्ड एवं 81 वय वंदन कार्ड, शंकरगढ़ में 318 आयुष्मान कार्ड एवं 47 वय वंदन कार्ड तथा कुसमी में 594 आयुष्मान कार्ड एवं 41 वय वंदन कार्ड बनाए गए।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के सभी पात्र राशन कार्डधारी परिवारों से अपील की है कि वे विशेष महाअभियान का लाभ उठाते हुए अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का आयुष्मान कार्ड तथा 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का वय वंदन कार्ड अवश्य बनवाएं। उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं मोबाइल नंबर साथ लाना आवश्यक है।

महतारी वंदन योजना की 30वीं किश्त जारी, महिलाओं के चेहरों पर खुशी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा आज महतारी वंदन योजना की 30वीं किश्त जारी किए जाने के बाद जिले की हितग्राही महिलाओं में खुशी का माहौल है। योजना के तहत प्राप्त एक हजार रुपये की मासिक सहायता राशि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

जिले की हितग्राही तेज कुमारी, मंजू रजवाड़े, पुनिया प्रजापति, शहनाज बेगम (सोहागपुर), गणेश्वरी प्रजापति (रामनगर), मेनका रजवाड़े तथा लता केंवट (रामनगर) ने विष्णु भैया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि उनके परिवार के लिए उपयोगी साबित हो रही है। हितग्राही महिलाओं ने बताया कि प्राप्त राशि का उपयोग वे अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा करने, पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी आवश्यक सामग्री खरीदने, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद तथा परिवार की अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में करेंगी। कुछ महिलाओं ने बताया कि वे इस राशि से अपने बच्चों का जन्मदिन भी मनाएंगी, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा।

महिलाओं ने कहा कि महतारी वंदन योजना ने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मविश्वासी बनाया है। हर माह मिलने वाली सहायता राशि से छोटे-छोटे आर्थिक कार्यों के लिए सहयोग मिलता है महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ''विष्णु भैया'' को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और परिवार की आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

ढाई साल की उपलब्धियाँ- छत्तीसगढ़ का श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में नई पहचान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर - पिछले ढाई साल में श्रम विभाग ने गढ़ी सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की मिसाल। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक ऐतिहासिक पहल की हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने श्रमिक कल्याण को केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सुशासन, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार से जोड़ते हुए श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। वहीं श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में विभाग ने श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ तेजी और सरलता से पहुंचाने के लिए व्यापक सुधार किए हैं।

ढाई साल की उपलब्धियाँ- छत्तीसगढ़ का श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में नई पहचान

श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में हो रहा है सुधार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, इन योजनाओ के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य में संगठित, असंगठित और निर्माण श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न श्रम कल्याण मंडलों के माध्यम से 67 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। श्रमिकों के पंजीयन, सहायता और योजनाओं के लाभ को अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाने के लिए श्रम विभाग ने नई यूजर-फ्रेंडली वेबसाइट श्रमेव जयते मोबाइल एप विकसित किया है, जिससे श्रमिक अब ऑनलाइन आवेदन, पंजीयन और अन्य सुविधाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर रहे हैं।

ढाई साल की उपलब्धियाँ- छत्तीसगढ़ का श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में नई पहचान

'रोजगार सृजन के साथ श्रमिक अधिकार भी हो रहा है मजबूत'

ढाई वर्षों में श्रम विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत किया है। 5 नए जिलों (मोहला-मानपुर-अंबागढ़, चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, ,सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

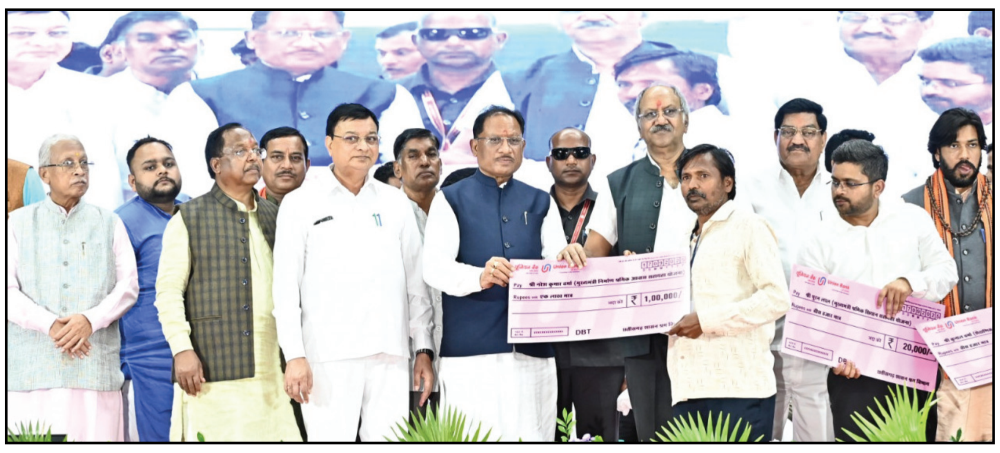

एवं सक्ती) में श्रम अधिकारी कार्यालय की स्थापना हेतु 20 पदों का सृजन किया गया है। वर्तमान में 10 जिलों के सहायक श्रमायुक्त कार्यालय तथा 23 जिलों में श्रम पदाधिकारी कार्यालय संचालित है। इस प्रकार राज्य के सभी 33 जिलों में श्रम कार्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न पदों पर नियुक्तियां कर विभागीय क्षमता को भी बढ़ाया गया है। उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। दुकानों एवं स्थापना अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, महिला श्रमिकों के लिए रात्रिकालीन कार्य की सुविधा, फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने जैसे अनेक निर्णयों ने रोजगार सृजन के साथ श्रमिक अधिकारों को भी मजबूत किया है।

'लगभग 17.82 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित'

श्रम विभाग की उपलब्धियों में सबसे उल्लेखनीय सफलता श्रमिक पंजीयन और हितलाभ वितरण रही है। 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2026 के बीच लगभग 12.65 लाख नए श्रमिकों का पंजीयन किया गया। लगभग 17.82 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया, जिन पर लगभग 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की गई। निर्माण श्रमिकों को लगभग 780 करोड़ रुपये तथा असंगठित श्रमिकों को लगभग 187 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। लाभ वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (ऊइळ) प्रणाली लागू की गई है।

मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र 24 घंटे, सात दिन संचालित

मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्रों की स्थापना श्रमिकों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र 24 घंटे, सात दिन संचालित किया जा रहा है। संचालित राज्यभर में मोबाइल शिविर आयोजित कर लाखों श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण और आवेदन संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के श्रमिकों को भी सरकारी सेवाओं का लाभ घर के समीप मिल रहा है। राज्य सरकार ने श्रमिक परिवारों के सामाजिक सुरक्षा कवच को भी मजबूत किया है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत आवास सहायता राशि बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की गई है। मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, छात्रवृत्ति, श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से हजारों परिवारों को आर्थिक संबल मिला है।

1.60 लाख से अधिक महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता

महिला श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र की 1.60 लाख से अधिक महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता प्रदान की गई। वहीं ह्लशहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजनाह्व के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रमिकों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेधावी शिक्षा सहायता, निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग तथा छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। हजारों विद्यार्थियों को इन योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे श्रमिक परिवारों के सपनों को नई उड़ान मिल रही है।

छत्तीसगढ़ का श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में नई पहचान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिक कल्याण को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का जो संकल्प लिया गया है, उसे श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में श्रम विभाग प्रभावी रूप से जमीन पर उतार रहा है। पारदर्शी व्यवस्था, तकनीकी नवाचार, त्वरित सेवा, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक सम्मान की भावना ने छत्तीसगढ़ को श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में नई पहचान दी है। ढाई वर्षों की यह यात्रा केवल योजनाओं और आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि लाखों श्रमिक परिवारों के जीवन में आए विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि की नई शुरूआत है।

आईपीएस पर 1 करोड़ की घूस लेने का आरोप, एएसआई और आरक्षक थे बिचौलिया

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर - जिले में पदस्थ ट्रेनी आईपीएस पर एक करोड़ रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि रिश्वत की रकम को हवाला के जरिए आईपीएस तक पहुंचाई गई थी। शिकायतकर्ता ने सीबीआई कोर्ट दिल्ली, सुधांशु कौशिक की अदालत में परिवाद दायर किया है। साथ ही इस मामले से जुड़ा व्हाट्सऐप चैट और ऑडियो क्लीप भी सौंपा है। पीड़ित की शिकायत के बाद कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी, सीबीआई निदेशक को नोटिस जारी किया। जानकारी के मुताबिक, हरियाणा निवासी आकाश कुमार पर अंबिकापुर के साइबर रेंज थाने में ठगी का केस दर्ज है। आकाश ने सीबीआई दिल्ली कोर्ट में परिवाद दायर कर बताया कि ठगी के केस की जांच के दौरान अंबिकापुर सीएसपी (कढर) राहुल बंसल ने दबाव बनाकर 1 करोड़ की मांग की। शिकायतकर्ता आकाश ने दावा किया कि रिश्वत की रकम हवाल नेटवर्क के जरिए कढर तक पहुंचाई गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। बातचीत का स्क्रीन शॉट और ऑडियो रिकॉर्ड भी अपने पास होने का दावा शिकायतकर्ता ने किया है।

शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने पूर्व में सीबीआई निदेशक को लिखित शिकायत देकर पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की थी, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पीड़ित ने शिकायत की कॉपी भी कोर्ट में पेश की है। कार्रवाई नहीं होने से दुखी शिकायतकर्ता ने दिल्ली सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में धारा 175 3, के तहत परिवाद दायर किया है। साथ ही आईपीएस राहुल बंसल, एएसआई प्रवीण राठौर, आरक्षक अंशुल शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7 ए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 308 और 351 के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की है। शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद सीबीआई कोर्ट ने आईपीएस समेत तीनों को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी

अगली सुनवाई 11 अगस्त को

बताया जा रहा हैं कि सीबीआई कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को 17 जुलाई को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी थी। मामले में डीजीपी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से एक माह का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और 22 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। अब कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। फिलहाल, आईपीएस पर 1 करोड़ के रिश्वत लेने के आरोप के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में हडकंप मचा हुआ है।

फर्जी दफ पेमेंट दिखाकर पेट्रोल पंप से ठगी करने वाला युवक गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायगढ़ । रायगढ़ जिले के जूटमिल थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर फर्जी ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर हजारों रुपये की ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी कार की नंबर प्लेट छिपाकर दो बार पेट्रोल भरवाता था और फर्जी क्यूआर भुगतान दिखाकर बिना पैसे दिए फरार हो जाता था। पुलिस ने आरोपी की बलेनो कार जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में जूटमिल पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की। पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को दरार्मुड़ा स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के संचालक अमित कुमार गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पिछले दो माह के दौरान एक युवक मारुति सुजुकी बलेनो कार से दो बार पेट्रोल भरवाकर फर्जी ऑनलाइन भुगतान का स्क्रीनशॉट दिखाकर फरार हो गया। पहली घटना 7 जून की रात हुई, जब आरोपी ने 2,500 का पेट्रोल भरवाया, जबकि दूसरी बार 25 जुलाई को 3,600 का पेट्रोल भरवाकर बिना भुगतान किए भाग निकला। दोनों घटनाओं में पेट्रोल पंप को कुल 6,100 का नुकसान हुआ। मामले में थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 429/2026 के तहत धारा 318(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल और मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरों तथा झलमला टोल प्लाजा के फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए

कार की आगे और पीछे की नंबर प्लेट पर काली पट्टी लगा रखी थी। वाहन के मिरर कवर और डिक्की के पास मरम्मत के निशान जैसे विशेष पहचान चिह्नों के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध वाहन सीजी-13-एक्यू-2394 को चिन्हित किया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से वाहन की पहचान कराने के बाद चालक मयंक शर्मा (19 वर्ष), निवासी बावलीकुआं, रायगढ़ से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने दोनों वारदातों को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त मारुति सुजुकी बलेनो कार और उसके दस्तावेज जब्त किए गए। जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि होने पर प्रकरण में धारा 318(4) बीएनएस भी जोड़ दी गई। पुलिस ने आरोपी को 6 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि धोखाधड़ी और छलपूर्वक संपत्ति हड़पने वाले अपराधियों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी विश्लेषण के माध्यम से ऐसे अपराधियों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा।

डीपीएस छिंदवाड़ा ने गोंदिया को 6-0 से हराकर फाइनल में किया प्रवेश

इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का आज होगा फाईनल मुकाबला

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। एमपावर इंटर स्कूल फुटबॉल टूनार्मेंट के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबले खेले गए। अंडर-14 और अंडर-19 वर्ग में विभिन्न स्कूलों की टीमों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अंडर-14 वर्ग में एलॉन्स पब्लिक स्कूल ने आरडब्ल्यूएस महासमुंद को 4झ0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। एसआरवीएम स्कूल, सूरजपुर और कोलंबिया स्कूल, रायपुर के बीच मुकाबला 1झ1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके बाद कोलंबिया स्कूल, रायपुर ने आरडब्ल्यूएस महासमुंद को 1झ0 से हराया, जबकि डीपीएस संबलपुर ने एलॉन्स पब्लिक स्कूल को 1झ0 से पराजित किया। अंडर-19 वर्ग में जेपी कांकेर ने एसआरवीएम स्कूल, सूरजपुर को 4झ0 से हराया। वहीं डीपीएस छिंदवाड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरडब्ल्यूएस गोंदिया को 6झ0 से शिकस्त दी। टूनार्मेंट के दौरान जिले के गणमान्य नागरिक एवं मीडिया प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। प्रमुख अतिथियों में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बलराम शर्मा, लोक अभियोजक राजू दास, प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवेश गोयल सहित मीडिया समूह से सुनील अग्रवाल, विनय मिश्रा, जानी खान, समरोज खान, विष्णु कसेरा, अमीर खान, कौशलेन्द्र यादव, प्रवीण साहू तथा नीरज साहू शामिल रहे। आयोजकों ने सभी प्रतिभागी टीमों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि टूनार्मेंट का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता के आगामी मुकाबलों को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है। उक्त तीन दिवसीय टूनार्मेंट का आज खिताबी व फाईनल मुकाबला खेला जाएगा। तीन दिनों के इस आयोजन का समापन साधुराम विद्या मंदिर प्रांगण में दोपहर 12 बजे संपन्न होगा।

उमेश पटेल या अमरजीत भगत को मिल सकती है पीसीसी की कमान

महंत और दीपक पर हाईकमान को है भरोसा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। जुलाई अंत में दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक समीकरण पर खासी चर्चा हो गई है। छत्तीसगढ़ से मिले फीड बैक और बैठक में मौजूद छत्तीसगढ़ के नेताओं के जवाब के आधार पर आगे की सियासी तस्वीर तय की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी छत्तीसगढ़ में सर्वेक्षण के जरिए संगठन और इससे जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्तताओं के बीच सामंजस्य को लेकर फीड बैक लिया था। सर्वे के बाद दीपक बैज से उनके कार्यकाल की पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। माना जा रहा था कि अगस्त 2026 या इसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान दूसरे नेता को सौंपी जा सकती है। इस लिहाज से दावेदार भी सक्रिय हो गए थे, मगर अब इस पर स्थिति साफ नहीं हो रही है। दिल्ली की बैठक में दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत दोनों मौजूद थे। बैठक में बैज ने संगठन के कामकाज, उठाए गए जनमुद्दों और आंदोलनों की एक विस्तृत रिपोर्ट आलाकमान के सामने रखी।

सूत्रों के मुताबिक, आलाकमान ने दीपक बैज के सांगठनिक ढांचे की जमकर तारीफ की है। बैज ने राज्य से जिला, ब्लॉक, मंडल और सीधे बूथ स्तर तक संवाद की ऐसी संरचना तैयार की है, जिसमें वे देश के अन्य राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से काफी आगे रहे। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां मंडल, बूथ और ग्राम पंचायत स्तर की कमेटियों का गठन सबसे पहले पूरा किया गया। हालांकि, इसमें निर्धारित 60 दिनों से थोड़ा अधिक समय लगा, लेकिन आलाकमान ने इस मॉडल को सराहा है। दिल्ली की बैठक के बाद अब पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 'जमीनी संवाद' का नया फॉमूर्ला लागू किया है। बैज को आम कार्यकताओं और जमीनी कैडर के बीच लगातार संवाद बढ़ाने का जिम्मा दिया गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत को विधायकों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी मिली है। डॉ. महंत ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है, वे खुद विधायकों के घर जाकर उनके और उनके परिवारों से व्यक्तिगत मुलाकात कर रहे हैं, ताकि पार्टी में एकजुटता बनी रहे।

क्यों टल सकता है कमान में बदलाव?

हालांकि अटकलें थीं कि बैज का कार्यकाल खत्म होने पर नया पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल दीपक बैज के हाथ में ही कमान रहने के आसार हैं। इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं गिनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी का संसद शेड्यूलः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फिलहाल संसद के सत्रों और राष्ट्रीय मुद्दों में व्यस्त हैं। पंजाब चुनाव पर फोकसः कांग्रेस का पूरा ध्यान 2027 की शुरूआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव पर है। भूपेश बघेल की नई भूमिकाः छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब का जिम्मा सौंपा गया है और वे लगातार वहां के दौरे कर रहे हैं। हालांकि दौरों के दौरान उन्हें पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों और गुटबाजी से भी जूझना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इन प्राथमिकताओं को देखते हुए माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष बदलने का फैसला अगले कुछ महीनों तक के लिए टाला जा सकता है। यदि आने वाले समय में आलाकमान बदलाव का मन बनाता है, तो नए अध्यक्ष के रूप में कई बड़े नाम दौड़ में हैं। ओबीसी कार्ड (उमेश पटेल): उमेश पटेल को इस रेस में सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हाल ही में जब राहुल गांधी रायपुर के पास चंपारण आए थे, तब उन्होंने उमेश पटेल से विशेष तौर पर लंबी बातचीत की थी। इस मुलाकात को सियासी गलियारों में यह संकेत माना गया कि भविष्य की कमान पटेल को सौंपी जा सकती है। आदिवासी चेहरा (अमरजीत भगत व मोहन मरकाम): चूंकि दीपक बैज खुद आदिवासी वर्ग से आते हैं, इसलिए यदि आदिवासी नेतृत्व को ही बरकरार रखा जाता है, तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नामों पर भी चर्चा जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस फिलहाल 'इंतजार और तैयारी' की मुद्रा में है। एक तरफ जहां भूपेश बघेल पंजाब में पार्टी की नैया पार लगाने में जुटे हैं, वहीं राज्य में दीपक बैज का मजबूत बूथ नेटवर्क और डॉ. चरणदास महंत का पारिवारिक संवाद पार्टी को जमीनी स्तर पर एकजुट कर रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की कमान दीपक बैज के पास ही सुरक्षित नजर आ रही है, लेकिन राष्ट्रीय समीकरणों के साफ होते ही प्रदेश कांग्रेस को नई दिशा मिलने के संकेत भी साफ हैं।

सम्पादकीय

सरकार युवाओं की आवाज सुने

जब बड़ी संख्या में देश के युवा किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी हर बात से सहमत होना सरकार के लिए जरूरी नहीं, लेकिन उनकी बात सुनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि युवाओं की बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार है, मौजूदा दौर में सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। विरोध को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर बल प्रयोग से दबाने के बजाय उसके पीछे के असंतोष को समझना लोकतांत्रिक शासन की पहली कसौटी होनी चाहिए। अगर कुछ भटके हुए युवक पत्थरबाजी जैसे रास्ते पर चले भी जाएं तो उन्हें केवल बल प्रयोग से नहीं, समझाने और काउंसलिंग के जरिए शांत करने के प्रयास किए जाने चाहिए। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से संयम बरतने की सलाह देते हुए कोर्ट ने सरकार को भी आक्रामक रवैये से बचने को कहा है। यह संदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विरोध व हिंसा के बीच एक स्पष्ट रेखा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति पर हमला, पत्थरबाजी या कानून तोड़ना स्वीकार नहीं किया जा सकता। चुनौती यह है कि राज्य इस फर्क को समझते हुए ऐसी नीति बनाएं, जिसमें कानून का राज भी कायम रहे और युवाओं की नाराजगी को संवाद का रास्ता भी मिले। दमन से तत्काल शांति दिख सकती है, लेकिन संवाद ही स्थायी समाधान की नींव रखता है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान की भावना के अनुरूप है, लेकिन हिंसा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती। 20 जुलाई के संसद मार्च में पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के घायल होने की घटना इसी संतुलन की जरूरत को सामने लाती है। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्थागत मंच है। उसकी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। यदि किसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा होती है, सुरक्षा घेरे को तोड़ने का प्रयास होता है या पुलिस पर हमला किया जाता है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कानून सबके लिए समान है और आंदोलन की आड़ में हिंसा को वैध नहीं बनाया जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि किसी आंदोलन की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। सरकार यदि पहले ही संवाद का रास्ता खोल दे तो कई बार वह स्थिति पैदा ही नहीं होती जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों का आमना-सामना हो। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि राज्य को संयम और संवाद दोनों को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाना चाहिए। पुलिस की भूमिका कानून-व्यवस्था बनाए रखने की है, लेकिन बल प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और सुरक्षा व्यवस्था का सम्मान करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार को भी दोहरी नीति से बचना होगा। एक ओर हिंसा करने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो और दूसरी ओर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत का रास्ता खुला रहे। आज जरूरत युवाओं को डराने की नहीं, उन्हें भरोसा देने की है। उनकी बात सुनी जाए, असहमति को लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाए और जहां शिकायत जायज हो, वहां समाधान की पहल हो। सरकार अगर युवाओं की आवाज सुनेगी तो उसे सड़कों पर टकराव कम और लोकतंत्र में भरोसा ज्यादा मिलेगा। यही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है।

अभियान
राजकुमार सिंह

सख्ती से ही संभव नशामुक्त भारत

> 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन नशे जैसी गहरी सामाजिक और आपराधिक समस्या का इलाज केवल जागरूकता से संभव नहीं। युवाओं को खेल, कला और संस्कृति से जोड़कर नशे से दूर रखने की कोशिश जरूरी है, मगर इसके साथ नशे की आपूर्ति करने वाले संगठित तंत्र पर कठोर प्रहार भी उतना ही अनिवार्य है। सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर देश के महानगरों और छोटे कस्बों तक ड्रग्स की उपलब्धता बताती है कि तस्करी का नेटवर्क अभी भी मजबूत है। इसलिए नशामुक्ति का संकल्प तभी सफल होगा, जब सरकार जागरूकता के साथ तस्करों, भ्रष्ट संरक्षण तंत्र और नशे के कारोबार की पूरी श्रृंखला पर निर्णायक कार्रवाई करे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत' संकल्प अभियान का स्वागत किया जाना चाहिए, पर तेजी से नासूर बनती जा रही इस समस्या का समाधान मात्र संदेश नहीं, सख्ती से ही संभव होगा। इस अभियान के अंतर्गत 100 सप्ताह तक हर रविवार को खेल, कला और संस्कृति आदि गतिविधियों के माध्यम से देश भर में युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सामाजिक संस्थाओं और औद्योगिक संगठनों के अलावा 100 से भी ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के सहयोग से यह अभियान चलाया जायेगा। जागरूकता की दृष्टि से यह निश्चय ही एक बड़ा अभियान होगा। तेजी से युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रही नशे की लत के विरुद्ध जागरूकता अभियान की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, पर स्वयं प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भारत में ड्रग्स की सप्लाई दुश्मन देशों की आतंकी साजिश का हिस्सा है। ऐसे में 100 रविवार जागरूकता अभियान मात्र चला कर नशामुक्त भारत का सपना आशावाद का ज्यादा नजर आता है। बेशक नशे की समस्या भारत में हाल-फिलहाल पैदा नहीं हुई। कभी पूर्वोत्तर से शुरू यह लत सीमावर्ती पंजाब और पड़ोसी हरियाणा तक पहुंच चुकी है। इससे अछूता रहने का दावा तो शायद ही कोई राज्य कर पाये, क्योंकि गुजरात के बंदरगाहों तक पर बड़ी-बड़ी खेप जब्त हुई हैं।

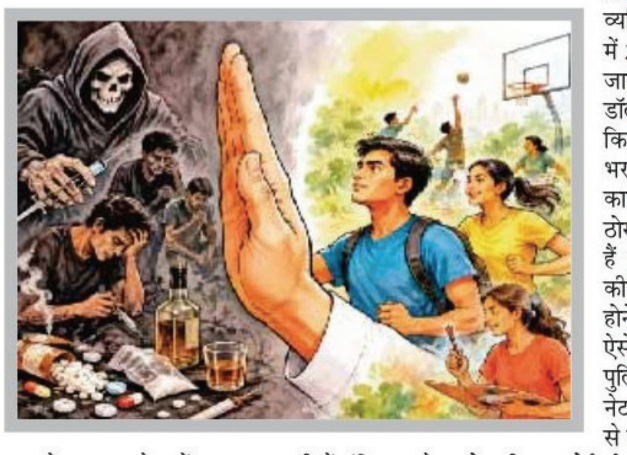

प्रधानमंत्री का दावा है कि ड्रग्स तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई पहले की तुलना में कई गुणा बढ़ी है, लेकिन तरह-तरह के ड्रग्स की देश के दूरदराज क्षेत्रों में भी सहज उपलब्धता सरकारी कार्रवाई को नाकाफी ही साबित करती है। यह तो खुला रहस्य है कि तमाम तरह का नशा सीमा पार से तस्करी हो कर ही भारत आता है। भारत की भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर यह काम दशकों से चल रहा है। सच यह भी है कि ड्रग्स तस्करी अब आतंकवादियों की फंडिंग का भी बड़ा स्रोत बन चुकी है। नापाक पड़ोसी पाकिस्तान हमारे देश में नशा तस्करी का एकमात्र स्रोत तो नहीं है, लेकिन शायद सबसे बड़ा स्रोत वही है। दरअसल विभाजन के जरिये अस्तित्व में आने के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध बहुआयामी छद्म युद्ध छेड़ रखा है। कश्मीर से पंजाब तक पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद का पालन-पोषण कर रहा है, बल्कि उसके लिए धन भी नशा तस्करी और जाली करंसी के जरिये भारत से ही जुटा रहा है। कहना नहीं होगा कि नशा तस्करी जहां भारतीय युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना रही है, वहीं जाली करंसी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रही है। बेशक भारत इस सबसे अनभिज्ञ नहीं है और हरसंभव कदम भी उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी दुष्चक्र को पूरी तरह तोड़ा नहीं जा सका है। सीमावर्ती पंजाब में युवाओं को नशे ने इस कदर खोखला कर दिया है कि उस पर 'उड़ता पंजाब' फिल्म भी बन चुकी है। पिछले कई चुनाव से पंजाब में नशा बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और पुलिस से ले कर राजनेताओं तक पर तस्करी में संलिप्तता के आरोप भी लगते रहे हैं, पर उससे मुक्ति का वायदा अभी तक कोई भी सरकार वफा नहीं कर पाई है। युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं। फिर भारत तो है ही युवा आबादी बहुल देश। ऐसे में युवाओं के नशे के दलदल में फंसने का दुष्प्रभाव देश के वर्तमान ही नहीं, भविष्य पर भी दूरगामी होगा। तमाम तरह के नशे जिस तेजी से भारतीय युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं, उसके आंकड़े डरावने हैं, पर उस पर अपेक्षित चिंता सरकारों और उनकी एजेंसियों में नजर आती नहीं। भारत का संविधान 'मद्य निषेध' की सोच रखता है, पर देश में 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग शराब पीते हैं, जिसकी जायज बिक्री के एवज में सरकारें मोटा राजस्व वसूलती हैं और शराब की बोतल एवं दुकानों पर चेतावनी लिखवा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती हैं। देश में लगभग तीन करोड़ लोग गांजे का सेवन करते हैं, जबकि दो करोड़ के आसपास हेरोइन आदि ड्रग्स का नशा करते हैं। आंकड़े तब और भी डरावने हो जाते हैं, जब पता चले कि इन नशाखोरों में किशोर और युवा भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। जाहिर है, नशा तस्करी जहां कानूनी चुनौती है, वहीं नशाखोरी एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गयी है, जिससे परिवार तबाह हो रहे हैं। इस समस्या से लड़ने और उबरने में मदद के लंबे-चौड़े दावे भी किये जाते हैं, लेकिन कड़वा सच यह है कि नशे की लत के शिकार 80-90 प्रतिशत लोगों को तो इलाज ही नहीं मिल पाता। ज्यादातर नशा मुक्ति केंद्र भी यातना केंद्र बन गए हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ही लगभग पौने छह करोड़ लोग शराब पीने से होनेवाली समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में भारत में प्रति व्यक्ति शराब की खपत 3.1 लीटर थी, जो 2023 में 3.2 लीटर हो गई और 2028 में 3.4 लीटर हो जाने की संभावना है। भारत में 60 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया शराब का बाजार बताता है कि कारोबारी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और सरकारें भरपूर राजस्व वसूल रही हैं। अन्य ड्रग्स का कारोबार गैर कानूनी है, इसलिए उसकी बाबत ऐसे ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि चोरी छिपे बिकनेवाली चीज मुंह मांगी कीमत पर ही मिलती है और उसके कारोबार से होनेवाला मुनाफा भी अकूत होता है। तभी तो लोग ऐसे जोखिमभरे कारोबार में दांव लगाते हैं और पुलिस-प्रशासन से ले कर खरीददारों तक अपना नेटवर्क बनाते हैं। ऐसे में नशाखोरी का मर्ज तेजी से नासूर ही बनता जा रहा है। वैसे तो इलाज की कोई ईमानदार कोशिश नजर आती नहीं, फिर भी सरकारी दावों पर भरोसा करें तो कहना पड़ेगाः 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की', पर अब तो मर्ज इलाज की हद से गुजर चुका है। अब इसकी शल्य चिकित्सा ही हो सकती है, जिसके लिए सबसे पहले व्यवस्था की शल्य चिकित्सा करनी होगी, क्योंकि बिना व्यवस्था के संरक्षण के ड्रग्स तस्करी सरीखा संगठित आपराधिक कारोबार भारत में फल-फूल ही नहीं सकता था। पूर्वोत्तर से ले कर पंजाब तक राजनेताओं और पुलिस-प्रशासन की संलिप्तता की चर्चाएं आम रही हैं, लेकिन इन खास लोगों की लगाम कसने का साहस अभी तक तो किसी ने नहीं दिखाया। अगर प्रधानमंत्री मोदी नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही भ्रष्ट व्यवस्था की शल्य चिकित्सा भी कर पाये, तो अवश्य नशा मुक्त भारत का सपना साकार हो सकता है। कोई भी देश अपने नागरिकों से ही विकसित बनता है। जब देश के नागरिक स्वस्थ्य, सभ्य तथा सामाजिक –आर्थिक रूप से खुशहाल होंगे, तभी सही मायने में विकसित भारत का

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

दिवस विशेष
डॉ.रमेश ठाकुर

'हिरोशिमा त्रासदी' की विभीषिका का दर्द

मानव इतिहास में '6 अगस्त 1945' की मनहूस तारीख को शायद ही कोई भूल पाए। 'हिरोशिमा दिवस' के रूप में मनाई जाती है ये तारीख। इस तारीख में सिर्फ तबाही लिखी थी। तारीख में ऐसा मुकर्रर वक्त था, जिसने मात्र 16 मिनट के भीतर 1,30,000 लोगों की सांसें एक साथ रोकी थी। हताहतों का आकंड़ा फिलहाल सरकारी है, पर वास्तिवक संख्या इससे कहीं अधिक बताई जाती है। हिरोशिमा पर किए परमाणु हमले में मरने वालों में बूढ़े, बच्चे, नौजवान, औरतें भी थीं। सुबह करीब 8:15 बजे अमेरिका ने हिरोशिमा पर अपने 'बी-29 'एनाला गे' विमान द्वारा आसमान से परिमाणु बमों की बारिश करके पूरा शहर जिंदा जला दिया था। घटना के वक्त ज्यादातर लोग सोए हुए थे, परमाणु बम ने उन्हें सोता ही मार दिया। हिरोशिमा में जब परमाणु बम फोड़ा गया, तो जापानियों को लगा कि सूरज फटा है। जबकि, वह सूरज नहीं, बल्कि तथाकथित विकसित, सभ्य और मुट्ठी भर लोगों का निर्णय तथा एक महाशक्ति द्वारा निर्मित कृत्रिम सूरज था, जिसकी आग में लाखों निर्दोष लोग भाप बनकर चंद मिनटों में उड़ गए। घटना का सामूहिक हत्यारा अमेरिका था। अगस्त माह की जब 6 तारीख आती है या फिर परमाणु हथियारों की बढ़ती तादात पर वैश्विक मंचों पर विमर्श होता है, तो जापान की दिल दहला देने वाली यह घटना आंखों के सामने अनायास उमड़ पड़ती हैं। घटना को श्रद्धांजलि के तौर पर ही सालाना 6 अगस्त को 'हिरोशिमा दिवस' के रूप में विश्व मनाता है। यह दिन उन मुल्कों को संकल्पित होने को आहवान भी करवाता है, जो परमाणु बम फोड़ने की अनावश्यक धमकी दिया करते हैं। साथ ही अहिंसा, त्रासदी, को छोड़कर भाईचारा अपनाने और शांति के पथ पर चलने को जागरूश्क भी करता है। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों पर गिराए गए अलग-अलग तारीखों पर परमाणु बम की यह कहानी काले अध्याय के रूप में तबतक दर्ज रहेगी, जबतक दुनिया इस धरती पर वास करेगी। 6 अगस्त को गिराए पहले बम का नाम 'एनाला गे' था। वहीं, 9 अगस्त वाले बम का नाम 'लिटिल बॉय' यानी यूरेनियम-आधारित परमाणु बम था। जापान का जब तक अस्तित्व रहेगा, उनके लोग अमेरिका को माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान, अमरिका जैसे मुल्क आज भी परमाणु बमों को फोड़ने की धमकी देते हैं। इसलिए हिरोशिमा दिवस उनके लिए चेतावनी के अलावा सीख जैसा भी है। हिरोशिमा की घटना को आज 81 वर्ष हो गए, लेकिन दुर्भाग्य संसार आज भी युद्ध-हिंसा में संलग्न है। यूं कहें कि परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठा है। हाल में, अमेरिका द्वारा ईराक पर परमाणु हमले की धमकी देना, दुनिया भर में बढ़ती हिंसा की घटनाएं और हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ के बीच हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि हम हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं से क्या कुछ सबक सीख पाए या नहीं? 81 साल पहले 2,50,000 हजार लोगों को मारकर भी अमेरिका को शांति नहीं मिली? अमेरिका की दादागिरी को जवाब देने का वक्त आ चुका है इसके लिए वैश्विक स्तर पर सभी मुल्कों को एकजुट होना होगा। साथ ही परमाणु हथियारों के निर्माणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की दिशा में सभी देशों को सामूहिक पहल करने की जरूरत है। गौरतलब है कि हिरोशिमा त्रासदी की ये तारीख निरस्त्रीकरण और आदर्शवादी की वह अवधारणा है जो पूरी तरीके से हथियारों की समाप्ति का समर्थन करती है। हालांकि, निरस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण कोई नई घटना नहीं है। इसको सर्वव्यापी मान्यता भले ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिली हो। पर, इसका मौजूदा वक्त में नियंत्रण खुराफाती मुल्कों ने खत्म कर दिया है। जबकि, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रों के मध्य निरस्त्रीकरण के लिए बकायदा समझौते भी हुए थे। हथियारों की मात्रा को घटाने में बहुत कुछ करने की जरूरत है। एकाध देश कुछ नहीं कर सकते। सभी को आगे आना होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद कभी कोई प्रयोग नहीं किया। भारत सदैव इस बात का पक्षधर रहा है कि परमाणु हथियारों का बेजा इस्तेमाल कभी ना किया जाए। इस मसले पर 26 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र ने अणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। उसके एक साल बाद फरवरी 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद द्वारा परंपरागत हथियार आयोग की स्थापना भी की गई। सन 1952 में महासभा ने उपर्युक्त दोनों आयोगों को संयुक्त करके निरस्त्रीकरण आयोग के नाम से एक नया आयोग भी बनाया। आयोग को परंपरागत और परमाणु दोनों प्रकार के हथियारों के नियमन के संदर्भ में संधि के प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मकसद सफल नहीं हुआ।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

गलतियों को खुले मन से स्वीकार करें

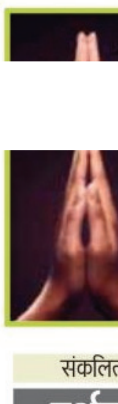

संकलित
दर्शन

कार्य संपन्न होने की प्रक्रिया में कदाचित त्रुटियां रह सकती हैं, भले ही कार्य निष्ठा से किया जाए। अगर कोई आपके किए-कराए में चूक निकाले, उस पर टिप्पणी करे तो नाराज होने के बजाय उसे खुलेमन से स्वीकार करें। वैसे आप गलतियां करने से तभी बच पाएंगे, जब कुछ नहीं करेंगे। अपने अवगुण या खोट को स्वीकार करना श्रेष्ठ मानवीय गुण है। औसत सोच का व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ होता है। अवांछनीय या अनुचित कार्य की अनदेखी का अर्थ है संशोधन के द्वार बंद कर देना। सर्वगुणसंपन्न व्यक्ति तो साक्षात देवता है। भूल-चूक की स्वीकारोक्ति प्रगति की राह में पहला चरण है। इस प्रक्रिया में आप अनेक व्यक्तियों का विश्वास जीतते हैं। जिस सत्य का सामना करने के लिए तैयार नहीं, उसे बदलेंगे कैसे? जिसे अपनी अपूर्णताओं का आभास नहीं वह मूर्ख नहीं, बल्कि दयनीय है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने अवगुणों को दूर नहीं कर सकेगा। जिस सीमा तक हम अपनी अपूर्णताओं और अवांछनीय व्यवहार के प्रति सजग रहेंगे और समाधान की ओर अग्रसर रहेंगे, उसी अनुपात में हम नैतिक रूप से समृद्ध होंगे। व्यावहारिक जीवन में संयमी, संयत व्यक्ति से भी भूल-चूक हो जाती है। उन्नत सोच का व्यक्ति अपनी भूल को तुरंत स्वीकार कर लेगा। मध्यम सोच वाले को गलती का अहसास तो होगा, वह मन में कुढ़ेगा भी, किंतु लज्जित होने की आशंका से वह गलती को खुलेआम नहीं मानेगा। अपनी छवि के प्रति अत्यंत चौकस अधिसंख्य

जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों?

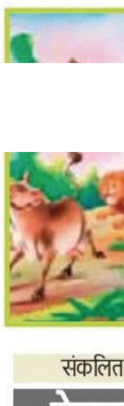

संकलित
प्रेरणा

एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। वह डर के मारे इधर-उधर भागने लगी। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम हुई थी। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे-धीरे धंसने लगी। बाघ भीधीरे-धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों भी करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वह बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूं। मेरा कोई मालिक नहीं। मैं खुद ही जंगल का मालिक हूं। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारे उस शक्ति का यहां पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिलकुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां पर नहीं पाएगा तो वह ढूंढते हुए यहां जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया।

अंतर्मन

आज की पाती

सरकारी धन का उचित प्रयोग करें सरकारें

देश में बहुत से राज्यों के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जैसे कि कहीं सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं अर्थात सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए इलाज की सुविधाएं नहीं, कहीं स्ट्रीट लाइट, कहीं सफाई व्यवस्था, कहीं पीने वाले पानी की समस्या, कहीं टूटी सड़के, लेकिन इनमें से कुछ राज्य बेवजह ही सरकारी पैसे को मुफ्त में लोगों को बांट रहे हैं। अगर इस सरकारी पैसे को ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए खर्च किया जाए तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, जो लोगों की साफ-सफाई, गरीबों को बीमारियों और अन्य बहुत सी समस्याओं को हल करेंगी। इसी तरह बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा पेंशन कम से कम 5000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। *- विजय शर्मा, रोहतक*

ट्रेंड

व्यापक बदलाव

सात वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 और 35ए इतिहास बन गए, जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास की नई शुरुआत हुई। दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी व लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिला। **-नरेंद्र मोदी,** पीएम

शीर्ष कोर्ट में 38 जज होंगे

न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, संवैधानिक एवं कानूनी व्याख्या के उभरते नए सवालों को ध्यान में रखकर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना समय की मांग है। अब शीर्ष अदालत में प्रधान न्यायायाधीश को मिलाकर कुल 38 न्यायाधीश हो जाएंगे। **-अर्जुन राम मेघवाल,** केंद्रीय मंत्री

गृहमंत्री जिम्मेदार

छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए भारत के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। उनमें न तो संसद में आकर इस मुद्दे पर बोलने का शिष्टाचार है और न ही यह बताने का साहस कि आखिर क्या हुआ। मुझे युवाओं और उन नौजवानों पर गर्व है, जिन्होंने संविधान, भारत की अवधारणा व देश के भविष्य की रक्षा के लिए आवाज उठाई। **-राहुल गांधी,** नेता विपक्ष

बुनियादी ढांचे का निर्माण

जेन-जेड को यह जानना चाहिए। महज 12 वर्षों में भाजपा-नीत सरकार ने भारत के आधुनिक बुनियादी ढांचे का 60-70 प्रतिशत से अधिक निर्माण किया है। शेष 30-40 प्रतिशत का निर्माण कांग्रेस-नीत सरकारों के करीब 60 वर्षों के शासन के दौरान हुआ। **-पेमा खांडू,** मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश

करंट अफेयर

मैसाचुसेट्स ने 15 अगस्त को 'इंडिया डे' किया घोषित

मैसाचुसेट्स की गवर्नर मॉरा हेली ने राज्य के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को मान्यता देते हुए 15 अगस्त को 'इंडिया डे' घोषित किया है और राज्य के निवासियों से इस अवसर के आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान किया। एक अगस्त को जारी सरकारी आदेश में गवर्नर ने यह भी कहा कि सामुदायिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने वार्षिक स्वतंत्रता दिवस समारोहों तथा सामुदायिक सेवा गतिविधियों के माध्यम से नागरिक भागीदारी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह की घोषणा बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने भी की है। उन्होंने भी 15 अगस्त को 'इंडिया डे' घोषित किया है। उन्होंने बोस्टन में भारतीय वाणिज्य दूतावास के नए कार्यालय के उद्घाटन का स्वागत किया और 'सेलबोस्टन-250' कार्यक्रम में भारतीय नौसैनिक पोत आईएनएस सुदर्शिनी के आगमन पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मैसाचुसेट्स की गवर्नर द्वारा जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि 15 अगस्त 2026 को भारत की ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से 1947 में मिली आजादी की 79वीं वर्षगांठ होगी।

ऑफ बीट

जानें कुछ ब्लैक होल दूसरों से बड़े क्यों?

ब्लैक होल घने खगोलीय पिंड होते हैं, जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी खुद में समेट लेते हैं, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता है। जो कुछ भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा को पार करेगा, वह ब्लैक होल में गिर जाएगा। इस गहरे, घने गड्ढे के अंदर, इसे फिर कभी नहीं देखा जा सकेगा। ब्लैक होल ब्रह्मांड में यहां-वहां फैले रहते हैं। हमारी आकाशगंगा जैसी आकाशगंगाओं में कुछ छोटे ब्लैक होल बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हैं। अन्य विशाल ब्लैक होल, जिन्हें 'सुपरमैसिव' ब्लैक होल कहा जाता है, आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित हैं। इनका वजन हमारे सूर्य के द्रव्यमान से दस लाख से एक अरब गुना तक हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे: खगोलशास्त्री संभवतः इतनी अंधेरी और इतनी बड़ी चीज़ कैसे देख सकते हैं? मैं एक खगोलशास्त्री हूं जो हमारे ब्रह्मांड में बने पहले सुपरमैसिव ब्लैक होल का अध्ययन करता है। मैं यह समझना चाहता हूं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं और वे किस प्रकार के खगोलीय माहौल में विकसित होते हैं। दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, अल्बर्ट आइंस्टीन और कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने सबसे पहले ब्लैक होल का विचार प्रस्तुत किया था।

खबर संक्षेप

छात्रसंघ चुनाव की मांग पर टकराव, कार्यकर्ता भिड़े

उदयपुर। यहां के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की

मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०

रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण रामप्यारी पति स्व० मोहर लाल यादव, भुपेन्द्र यादव, योगेन्द्र यादव आ.स्व. मोहर लाल यादव, सभी जाति बरगाह निवासी दरीपारा अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदकगण के पति/पिता मोहर लाल यादव के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ०पुर, मोहल्ला दरीपारा स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 4018/46 रकबा 1220 वर्गफीट भूमि है। भूधारक मोहर लाल यादव की मृत्यु दिनांक 04.03.2021 को हो गई है तत्पश्चात आवेदकगण द्वारा आवेदित भूमि से मृत्तक मोहर लाल यादव का नाम विलोपित करते हुये स्वयं के नाम से फौती नामांतरण किये जाने हेतु मृत्तक मोहर लाल यादव के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 29/08/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत स्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07/08/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए

असम में एनएच-15 पर बनेगा 4-लेन हाईवे 'गोबरधन' योजना से किसान होंगे लाभान्वित

यह प्रोजेक्ट एनएचओ के तहत 8970.20 करोड़ की लागत से 'बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर' टोल मोड पर डेवलप होगा। इसमें तेजपुर बाइपास पर 4.9 किमी लंबा इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का निर्माण होगा।

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने गुरुवार को कई अहम और बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने असम में एनएच -15 पर गुवाहाटी के पास बैहाटा चारियाली से तेजपुर तक 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दी है। बैहाटा चारियाली से तेजपुर तक बनाए जाने वाले इस 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे की लंबाई 135.871 किमी होगी। यह प्रोजेक्ट एनएचओ के तहत 8970.20 करोड़की कुल लागत से 'बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर' टोल मोड पर डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में तेजपुर बाईपास पर 4.9 किमी लंबा एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का निर्माण भी शामिल है, जिसे भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दी फैसलों की जानकारी

योजना को भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया गया

15 बड़े पुल, 30 छोटे पुल, 19 फ्लाईओवर और 1 हाथी अंडरपास बनाने का प्रावधान

इसके अलावा प्रोजेक्ट में 15 बड़े पुल, 30 छोटे पुल, 19 फ्लाईओवर और 1 हाथी अंडरपास (तेजपुर बाइपास में) बनाने का प्रावधान है। चूंकि इस प्रोजेक्ट को एक्सेस-कंट्रोल्ड बनाया जा रहा है, इसलिए ट्रैफिक की आवाजाही बनाए रखने के लिए 46 अंडरपास, 19 फ्लाईओवर और 210 किमी सर्विस रोड का निर्माण भी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से यात्रा का समय आधा हो जाएगा, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और गाड़ी चलाने का खर्च भी कम होगा।

कम्प्रेस्ड बायोगैस को विस्तार देने मजबूत ढांचा मुहैया होगा

योजना के तहत कृषि अपशिष्ट, पशुओं का गोबर, गन्ने की खोई, शहरी जैविक कचरा और अन्य बायोमास संसाधनों को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद, ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में बदला जाएगा। सरकार ने कहा कि सुनिश्चित मांग, आकर्षक एवं स्थिर मूल्य निर्धारण, पूंजीगत सहायता, पाइपलाइन अवसंरचना, ऋण समर्थन और प्रौद्योगिकी विकास जैसे उपायों के जरिये ये योजना कम्प्रेस्ड बायोगैस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने मजबूत एवं स्पष्ट ढांचा मुहैया होगा।

सीबीजी उत्पादन को बढ़ाया जाएगा

यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी और भारत की ऊर्जा व्यवस्था में संपीड़ित बायोगैस को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित करेगी। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से देश में सीबीजी उत्पादन को करीब 10 गुना बढ़ाना, निजी निवेश आकर्षित करना और सर्कुलर बायोइकोनॉमी को मजबूत करना है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के तहत सीबीजी उत्पादकों को सुनिश्चित बाजार, स्थिर मूल्य, पूंजी सहायता दी जाएगी।

योजना के 6 प्रमुख घटक

1. सुनिश्चित सीबीजी खरीद
2. स्थिर मूल्य व्यवस्था
3. पूंजी सहायता
4. पाइपलाइन अवसंरचना का विकास
5. क्रेडिट गारंटी सुविधा
6. सीबीजी इकोसिस्टम

23,731 करोड़ की गोबरधन योजना को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने गुरुवार को देश में बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 23,731 करोड़ रुपए के प्रावधान वाली राष्ट्रीय एकीकृत योजना 'गोबरधन' को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि 'गोबरधन' योजना को 2026-27 से 2035-36 तक लागू किया जाएगा और इसका उद्देश्य कम्प्रेस्ड बायोगैस को देश के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख स्तंभ बनाना है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ

यह योजना किसानों, सहकारी समितियों, फीडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगी। साथ ही कृषि अवशेष, गोबर और शहरी जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।

प्रयागराज में कल होनी थी सभा

कार्यक्रम की मंजूरी नहीं, आवाज उठाने से रोक नहीं सकतेः राहुल

'छात्रों की गूंज' को मंजूरी आखिरी समय में रद्द कर दी

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। 8अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम की मंजूरी आखिरी समय में रद्द कर दी गई। राहुल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें छात्रों के हक की आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। अनुमति रद्द होने के पीछे कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश, लगातार बारिश से जलभराव और जिला प्रशासन से अंतिम मंजूरी नहीं मिलने का हवाला दिया है। इसमें पेपर लीक, फीस बढ़ोतरी, सीटों में कटौती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी।

प्रियंका ने केंद्र पर साधा निशाना

'किस बात का डर?

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए स्थल की अनुमति नहीं मिलने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन इस कार्यक्रम से किस बात से डर रहा है। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र में, कायस्थ पाठशाला के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि यह निर्णय प्रधानाध्यापक की जानकारी के बाद और उच्च न्यायालय के आदेश पर रद्द की है।

सरकार एथेनॉल 50 फीसदी तक बढ़ाएगी

ई-20 पर विवाद

आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और भाजपा के आईटी विभाग प्रमुख अमित मालवीय के बीच एक्स पर तीखी बहस सामने आई। केजरीवाल ने केंद्र पर डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन में एथेनॉल मिश्रण करने की योजना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ई20 ईंधन के बाद पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 50 फीसदी से अधिक बढ़ाएगी। केजरीवाल ने नए पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने से बचने का आग्रह किया।

ई 20 से आगे कोई फैसला नहीं लिया गया

भाजपा आईटी सेल के अमित मालवीय ने केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र ने ई20 से आगे मिश्रण बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने केजरीवाल के तर्क को तथ्यों के बजाय भय पर आधारित बताया। ई20 बिना वैज्ञानिक स्टडी के लागू नहीं किया था।

जेपीएससी-जेएसएससी में गड़बड़ी पर आंदोलन

सरकार से बातचीत के लिए डेलिगेशन किया तय 8 छात्र, 1 वकील और 2 एक्सपर्ट करेंगे बात

सभी मांगें और तथ्य केवल छात्र प्रतिनिधि सरकार के सामने रखेंगे

एजेंसी ▶▶ रांची

जेपीएससी और जेएसएससी समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र आंदोलन के बीच सरकार से वार्ता को लेकर बड़ी खबर है। छात्रों ने प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी की है। इससे राज्य सरकार के साथ बातचीत होगी। प्रतिनिधिमंडल में 8छात्र प्रतिनिधियों के अलावा 2पत्रकार और 1 वकील को शामिल किया गया।

माइक, कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइस बैन

आंदोलनकारियों ने कहा कि पत्रकार और कानूनविद केवल अभिभावक एवं मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। बैठक के दौरान किसी भी मुद्दे, मांग या तथ्य को केवल छात्र प्रतिनिधि ही सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पत्रकार और कानूनविद बयान नहीं देंगे। बैठक में माइक, कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइस बैन रहेंगा।

आंदोलनकारी छात्रों ने मांगा हेमंत का इस्तीफा, वे पद के लिए अयोग्य

झारखंड में विरोध-प्रदर्शन गुरुवार को 13वें दिन में प्रवेश कर गया। उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर छह प्रदर्शनकारी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं सरकार की ओर से गंभीरता नहीं दिखाने पर अब आंदोलनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर दी है। राज्य सरकार उनकी मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है।

---

20 दिन में 8 जगह धंसी सड़क

नई दिल्ली। कानपुर एक्सप्रेसवे के लगातार धंसने पर एनएचएआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा को हटा दिया। निर्माण कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक पर भी कार्रवाई शुरू हुई है। मरम्मत पूरी होने तक एक्सप्रेसवे टोल फ्री रहेगा और गुणवत्ता की जांच आईआईटी खड़गपुर करेगा। अगस्त के पहले हफ्ते तक एक्सप्रेसवे आठ स्थानों पर उखड़ा और धंसा।

शपथ पत्र

मैं श्रीमती कंचन दास पति स्व. कवि दास उम्र 45 वर्ष, निवासी भाथुपारा, अम्बिकापुर थाना व तह. अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०. निम्नांकित कथन शपथ पूर्वक करती हूंः- मैं शपथ पूर्वक कथन करती हूं कि मेरी पुत्री मालती दास का आधार कार्ड नं-9188 7524 5564 है जिसमें उसका नाम मानती तथा जन्मतिथि 01.01.2010 दर्ज है. जो गलत है। मैं पथ पूर्वक कथन करती हूं कि मेरी पुत्री का सही नाम कु. मालती दास तथा जन्म तिथि 15.07.2009 है, जो उसके अंकसूची में दर्ज है। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में अंकित नाम तथा जन्मतिथि को सुधार कर सही नाम कु. मालती दास तथा जन्म तिथि 15.07.2009 दर्ज किया जाये, जिसके संबंध में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर रही हूं।

सत्यापन
ह०शपथकर्ता

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०

रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती हेमा गुप्ता पत्नी अमर कुमार गुप्ता, उम्र 45 वर्ष, निवासी साईं इन हॉटल के पास, जैन मंदिर रोड, डालटेनगंज, जिला पलामू, झारखण्ड के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है. कि आवेदिका के द्वारा अनावेदक सुनील कुमार सोनी पिता शंकर प्रसाद सोनी, उम्र 40 वर्ष निवासी भगवानपुर तह० अ०पुर जिला सरगुजा छ०ग० के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ०पुर, शीट नं. 11 मोहल्ला सदर रोड़ स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 3196/4817/54 रकबा 385.06 वर्गफीट एवं प्लॉट नं0 3196/4817/64 रकबा 195 वर्गफीट भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 08.07.2026 के माध्यम से क्रय किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर आवेदिका द्वारा क्रयशुदा भूमि का नामांतरण स्वयं के नाम से किये जाने हेतु पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 24/08/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 07/08/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

शपथ पत्र

मैं इंजोरिया पति अमर साय उम्र लग0-21 वर्ष, जाति गोंड़ निवासी सांवारांवा तहसील भैयाथान जिला- सूरजपुर (छ.ग.) की निम्नांकित शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि मैं शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि मैं उपरोक्त पते की निवासी हूँ, तथा मेरे नाम से आधार कार्ड क्रमांक-7824 2367 4662 बना है, जिसमें त्रुटिवश मेरा नाम उजरिया (UJARIYA) एवं जन्मतिथि- 01/01/2004 अंकित है। जो त्रुटिपूर्ण है। मैं शपथ पूर्वक कथन करती हूँ, कि मेरे कक्षा 10 वीं के अंकसूची स. क्रमांक- 21090788 में मेरा नाम इंजोरिया (INJORIYA) एवं जन्मतिथि- 07/10/2005 अंकित है, जो पूर्णतः सत्य एवं सही है।

मैं शपथ पूर्वक कथन करती हूँ, कि अपने अधार कार्ड में अंकित त्रुटिपूर्ण नाम एवं जन्मतिथि को विलोपित कराकर, अपने कक्षा 10 वीं के अंकसूची प्रमाण पत्र में अंकित वास्तविक नाम एवं जन्मतिथि के आधार पर अपने आधार कार्ड में नाम एवं जन्मतिथि सुधार कराना चाहती हूँ, जिसके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ।

ह०/ शपथकर्ता

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी बरियों जिला बलरामपुर रा०गंज छ०ग०

रा०मा०क्र०- /ब-121/2025-26

ग्राम- खोडरो प०ह०नं०- उप तह० बरियों

ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम खोडरो प०ह०नं०- उप तहसील बरियों जिला बलरामपुर रा०गंज को सूचित किया जाता है कि आवेदक भीम सिंह आ०/पति.. धनी राम जाति गोंड़ निवासी ग्राम खोडरो तहसील राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा स्वंय के दादी बिफनी पावले का मृत्यु दिनांक 11.11.2021 को ग्राम खोडरो घर में हुई है। किन्तु जन्म मृत्यु पंजीयन कार्यालय में नियत समय में अज्ञानता वश कार्य व्यस्तता के कारण पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र पेश। उपरोक्त जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में उज्जर आपत्ति या दावा हो या हितबद्ध पक्षकार हो तो वह स्वंय, अथवा वैध अभिकर्ता अथवा अभिभाषक के दिनांक-21/7 / 2026 को न्यायालयीन समय में दावा या आपत्ति हो तो पेश कर सकता है। नियत तिथि पश्चात प्राप्त दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अतः आज दिनांक- 13/7/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
बरियों जिला बलरामपुर रा०गंज

मझवां के प्रदुम कुमार सरोज ने लखनऊ में मंत्रियों से की मुलाकात

मिजार्पुर। मझवां विधानसभा क्षेत्र निवासी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सरोज के भांजे प्रदुम कुमार सरोज ने लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मिजार्पुर जनपद और मझवां विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों, शिक्षा, श्रमिक हितों तथा ग्रामीण समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। प्रदुम कुमार सरोज ने बताया कि उनकी मुलाकात विभिन्न विभागों के मंत्रियों से हुई, जिनके समक्ष क्षेत्र की आवश्यकताओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि उद्देश्य मिजार्पुर के विकास कार्यों को गति दिलाना तथा जनता की समस्याओं का समाधान कराना है। इन मंत्रियों से हुई मुलाकात और प्रमुख मुद्दे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। मझवां एवं मिजार्पुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और विकास योजनाओं में तेजी लाने की मांग रखी गई। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से औद्योगिक विकास एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। मिजार्पुर में निवेश, विकास और प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई।

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी बरियों जिला बलरामपुर रा०गंज छ०ग०

रा०मा०क्र०- /ब-121/2025-26

ग्राम- खोडरो प०ह०नं० - उप तह० बरियों

ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम खोडरो प०ह०नं०- उप तहसील बरियों जिला बलरामपुर रा०गंज को सूचित किया जाता है कि आवेदक भिम सिंह आ०/ पति.. धनी राम जाति गोंड निवासी ग्राम खोडरो तहसील राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा स्वंय के दादा भेंटल राम आ० छेरतु राम का मृत्यु दिनांक 16.10.2008 को ग्राम खोडरो घर में हुई है। किन्तु जन्म मृत्यु पंजीयन कार्यालय में नियत समय में अज्ञानता वश कार्य व्यस्तता के कारण पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र पेश।उपरोक्त जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र में उज्जर आपत्ति या दावा हो या हितबद्ध पक्षकार हो तो वह स्वंय, अथवा वैध अभिकर्ता अथवा अभिभाषक के दिनांक- 21/7 / 2026 को न्यायालयीन समय में दावा या आपत्ति हो तो पेश कर सकता है। नियत तिथि पश्चात प्राप्त दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अतः आज दिनांक-13/7/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
बरियों जिला बलरामपुर रा०गंज

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी बरियों जिला बलरामपुर रा०गंज छ०ग०

रा०मा०क्र०- /ब-121/2025-26

ग्राम बरियों प०ह०नं०- उप तह० बरियों

ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम बरियों प०ह०नं० उप तहसील बरियों जिला बलरामपुर रा०गंज को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामचरन आ०/पति.. अली जाति घासी निवासी ग्राम बरियों तहसील राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा स्वंय के पिता अली आ० लुरन का मृत्यु दिनांक 03.02.2011 को ग्राम बरियों घर में हुई है। किन्तु जन्म मृत्यु पंजीयन कार्यालय में नियत समय में अज्ञानता वश कार्य व्यस्तता के कारण पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र पेश। उपरोक्त जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में उज्जर आपत्ति या दावा हो या हितबद्ध पक्षकार हो तो वह स्वंय, अथवा वैध अभिकर्ता अथवा अभिभाषक के दिनांक- 22/6/2026 को न्यायालयीन समय में दावा या आपत्ति हो तो पेश कर सकता है। नियत तिथि पश्चात प्राप्त दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अतः आज दिनांक-17/6/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
बरियों जिला बलरामपुर रा०गंज

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी बरियों जिला बलरामपुर रा०गंज छ०ग०

रा०मा०क्र०- /ब-121/2025-26

ग्राम बरियों प०ह०नं०- उप तह० बरियों

ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम बरियों प०ह०नं०- उप तहसील बरियों जिला बलरामपुर रा०गंज को सूचित किया जाता है कि आवेदक सफीरन आ०/पति. आमिरसाय जाति घासी निवासी ग्राम बरियों तहसील राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा स्वंय के पिता आमिरसाय आ० रोन्दा का मृत्यु दिनांक 06.05.2010 को ग्राम बरियों घर में हुई है। किन्तु जन्म मृत्यु पंजीयन कार्यालय में नियत समय में अज्ञानता वश कार्य व्यस्तता के कारण पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र पेश। उपरोक्त जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र में उज्जर आपत्ति या दावा हो या हितबद्ध पक्षकार हो तो वह स्वंय, अथवा वैध अभिकर्ता अथवा अभिभाषक के दिनांक 22/06/2026 को न्यायालयीन समय में दावा या आपत्ति हो तो पेश कर सकता है। नियत तिथि पश्चात प्राप्त दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अतः आज दिनांक- 10/6/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
बरियों जिला बलरामपुर रा०गंज

मेरा गांव-स्वास्थ्य संपन्न गांव अभियान के तहत स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

संवाददाता

ठाणे : महाराष्ट्र शासन के महत्वाकांक्षी ₹मेरा गांव-स्वास्थ्य संपन्न गांव₹ अभियान के अंतर्गत ठाणे जिले में अगस्त 2026 के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, निवारक उपाय, रोग नियंत्रण अभियान तथा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां प्रभावी रूप से आयोजित की जाएंगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक गांव को स्वच्छ, स्वस्थ, रोगमुक्त एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से सशक्त बनाना है। ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, आशा स्वयंसेविकाएं, आंगनवाड़ी सेविकाएं, स्वास्थ्य कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा। यह अभियान जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। जिला शल्य चिकित्सक डॉ. कैलास पवार तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के सभी तालुकों में इसकी योजनाबद्ध रूप से प्रभावी क्रियान्विति की जाएगी। इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव ने कहा, ₹स्वस्थ गांव ही सशक्त और समृद्ध समाज की आधारशिला है। मेरा गांव-स्वास्थ्य संपन्न गांव अभियान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक निवारक स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य जागरूकता और समय पर उपचार पहुंचाने का हमारा प्रयास है। ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य तंत्र और ग्रामीणों की सामूहिक भागीदारी से यह अभियान और अधिक प्रभावी बनेगा। प्रत्येक नागरिक स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, स्वच्छता तथा रोगों की रोकथाम संबंधी उपायों में सक्रिय भागीदारी निभाकर अपने गांव को स्वास्थ्य की दृष्टि से सशक्त बनाए।₹ जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत रोगों की शीघ्र पहचान, जनजागरूकता, नियमित स्वास्थ्य जांच तथा निवारक उपायों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

हायर सेकेंडरी बोझा में निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना का हुआ आगाज

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोझा में शासन की निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत कक्षा 9 वीं की नव प्रवेशी छात्राओं को क्षेत्रीय विधायक श्रीमती शकुंतला सिह पोर्ते के हाथो साइकिल वितरित की गई। विधायिका के द्वारा कहा गया कि यह साइकिल केवल एक साधन नहीं, बल्कि बेटियों की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और उज्वल भविष्य की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम है। अब हमारी बेटियाँ समय पर विद्यालय पहुँचकर अपने सपनों को नई उड़ान देंगी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने छात्राओं को शिक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए निरंतर अध्ययन, अनुशासन एवं सफलता की ओर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया।विद्यालय के प्राचार्य अकबर कुरैशी ने विद्यालय के नव प्रवेशी छात्रो को संबोधित करते हुए बताया कि शिक्षित बेटी, सशक्त समाज यही है विकसित भारत की पहचान। के साथ माननीय विधायक एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का महोदय के द्वारा नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाते हुए नवीन पाठ्यपुस्तक भेंट स्वरूप दिया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य सहित अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर अपने शिक्षकों और प्राचार्य सहित अपने माता-पिता का नाम रोशन करने की सलाह दी, उन्होंने शिक्षा है जरूरी के थीम पर बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय में आने और अपने शिक्षकों के साथ सादगीपूर्ण व्यवहार करते हुए शिक्षा ग्रहण करने तथा अपना कुशल व्यवहार रखते हुए विद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु प्रेरित किया साथ ही नशा मुक्ति अभियान विकसित भारत हेतु विद्यालय में 500संख्या में उपस्थित छात्र छात्राओं एवं उपस्थित अभिभावकों को शपथ दिलाई गई। विद्यालय की छात्रा कुमारी सपना ने विगत वर्ष छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित प्रेरणा कार्यक्रम अंतर्गत व्याख्याता संतोष भारती, श्रीमती मंजुला निकुंज के देखरेख में भाग ली जिसमें छत्तीसगढ़ से एकमात्र बालिका चयनित होकर प्रेरणा कार्यक्रम पर राजस्थान शैक्षिक और सांस्कृतिक भ्रमण की थी, तथा छात्र ने यातायात सप्ताह अंतर्गत जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर नगद राशि इनाम स्वरूप जीती थी जिसे चेक के माध्यम से माननीय विधायक का महोदय के द्वारा वितरण किया गया, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक शकुंतला सिंह सहित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती

चंद्रमणि पैकरा शाला प्रबंधन विकास समिति के अध्यक्ष श्री धनेश्वर राजवाड़े ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती बालमति टेकाम उप सरपंच श्री खगेश मिश्रा शाला प्रबंधन विकास समिति उपाध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मिश्रा, श्री समय लाल मिश्रा सांसद प्रतिनिधि, गुलाब मिश्रा, संजय मिश्रा मंत्री भाजपा किसान मोर्चा जरही, ज्योतिष मिश्रा, हीरालाल मिश्रा, काशी प्रसाद मिश्रा, धनेश्वर, एवं सभी विशिष्ट अतिथि प्राचार्य संकुल समन्वयक मान साय राजवाड़े, रामेश्वर राजवाड़े, मुन्ना लाल राजवाड़े ,एवं समस्त माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला सभी स्टाफ की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ कार्यक्रम का सफल संचालन एल. पी .तिवारी सांस्कृतिक प्रभारी आलोक लकड़ा एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोझा के स्टाफ के सहयोग से सम्पन्न हुआ।

79 साल बाद भी अंधेरे में 38 गांव, बिजली की मांग पर आप ने किया धरना प्रदर्शन

दिया 30 दिन का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं हुई तो मंत्री आवास घेराव की चेतावनी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

चांदनी-बिहारपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र के 38 गांवों में बिजली सुविधा की मांग को लेकर शुक्रवार को बिहारपुर थाना के सामने आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। बिजली अधिकार आंदोलन₹ के तहत आयोजित एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन में सैकड़ों ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। आंदोलन के दौरान दिनभर कड़ी धूप और बाद में हुई मूसलाधार बारिश भी प्रदर्शनकारियों का हौसला नहीं तोड़ सकी। बारिश के बीच भी ग्रामीण ₹बिजली हमारा अधिकार है, 79 साल बाद भी अंधेरे में क्यों? और झांसे में नहीं आना है, क्षेत्र में बिजली लाना है₹ जैसे नारों के साथ धरने पर डटे रहे। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि आजादी के 79 वर्ष बाद भी क्षेत्र के कई गांव मूलभूत सुविधा बिजली से वंचित हैं। ग्रामीणों को अब भी अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि लगातार मांग और आश्वासन के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा सचिव लव कुमार ने कहा कि सितंबर से बिजली

कार्य शुरू होने की खबरें प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से मिली जानकारी इससे अलग है। उन्होंने कहा कि यदि 30 दिनों के भीतर सभी शेष गांवों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और कार्यवाही शुरू नहीं हुई तो पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। साथ ही क्षेत्र की विधायक एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री के निवास का लोकतांत्रिक घेराव तथा प्रतीकात्मक रूप से बिजली काटने का आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। जिला संगठन महासचिव पुनीत दुबे ने दावा किया कि प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के कुल 28 गांवों में से केवल 11 गांवों को ही प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। शेष 17 गांवों के लिए न तो स्वीकृति जारी हुई है और न ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत 11 गांवों के लिए 24 अगस्त को टेंडर खोले जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी है। जिलाध्यक्ष रवि जायसवाल ने कहा कि सितंबर से सभी गांवों में बिजली कार्य शुरू होने के दावे वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते। उन्होंने सरकार से शेष गांवों के लिए भी तत्काल प्रशासनिक स्वीकृति, बजट और टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की मांग की ताकि सभी गांवों में एक साथ विद्युतीकरण कार्य शुरू हो सके। धरना-प्रदर्शन के समापन पर आम आदमी पार्टी ने प्रशासन को 30 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि तय समय के भीतर सभी लंबित गांवों के लिए स्वीकृति और कार्य प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। प्रदर्शन में लोकसभा सचिव लव कुमार, जिलाध्यक्ष रवि जायसवाल, जिला संगठन महासचिव पुनीत दुबे, अजय घोष, चंद्रबली राजवाड़े, संदीप यादव, राकेश जायसवाल, गजमोचन सिंह, लक्ष्मण जायसवाल, तुलसी जायसवाल, सुरेश देवांगन, सर्वेश गुप्ता, माया सिंह, सुनील जायसवाल, आशीष कुशवाहा, खगेश्वर चौधरी, श्यामबिहारी कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

खाद घोटाले की जांच में बड़ा एक्शन, अब गोदाम प्रभारी निलंबित

करोड़ो के घोटाले की आशंका, कार्रवाई की जद में आ सकते है और भी कर्मचारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के सहकारी समिति जयनगर में व्यापक पैमाने पर हुए खाद घोटाले की जांच लगातार नए खुलासे कर रही है। समिति प्रबंधक के निलंबन और अध्यक्ष से बोर्ड की शक्तियां वापस लेने के बाद अब कार्रवाई की आंच मार्कफेड के गोदाम तक पहुंच गई है। विश्रामपुर-प्रतापपुर स्थित डबल लॉक खाद गोदाम के प्रभारी एवं क्षेत्र सहायक लिवेन खेस्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा 27 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया है कि

विश्रामपुर, प्रतापपुर स्थित डबल लॉक खाद गोदाम में भंडारित रासायनिक उर्वरकों के भौतिक सत्यापन के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। जांच में खाद के भंडारण और वितरण में गंभीर विसंगतियां तथा अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। आदेश के अनुसार, गोदाम में उपलब्ध खाद का भौतिक सत्यापन करने पर ऑनलाइन दर्ज स्टॉक और वास्तविक उपलब्ध खाद की मात्रा में उल्लेखनीय कमी पाई गई। इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ सेवा नियम, 2007 के तहत लिवेन खेस्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय जशपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले जयनगर सहकारी समिति में खाद स्टॉक में लगभग 35 से 40 लाख रुपये मूल्य की कमी मिलने के बाद समिति प्रबंधक को निलंबित किया गया था। वहीं समिति अध्यक्ष से भी बोर्ड की शक्तियां वापस ले ली गई थीं। किसानों की शिकायत थी कि खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी, जबकि रिकॉर्ड में स्टॉक दशार्या जा रहा था। इसी शिकायत के बाद जांच शुरू हुई थी। अब गोदाम प्रभारी के निलंबन से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि जांच केवल समिति तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद भंडारण, आपूर्ति और वितरण की पूरी श्रृंखला की जांच की जा रही है। सूत्रों की मानें तो आने वाले दिनों में इस मामले में और भी जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह मामला अब जिले के सबसे चर्चित खाद घोटालों में शामिल हो गया है और किसान भी जांच पूरी होने के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

ब्लैड से हमला कर पत्नि की गर्दन काटने वाला आरोपी गिरफ्तार

कुदरगढ़ पुलिस की कार्रवाई

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। पत्नी के गर्दन पर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी पति को जिले की कुदरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात बीते गुरुवार को भंवरखोह के तेलईडांड में हुई है। बताया गया है कि 6 अगस्त को ग्राम भंवरखोह तेलईडांड के हरदयाल सिंह ने चौकी कुदरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी भांजी आहता अपने 7 बर्षीय पुत्र के साथ इसके घर भवंरखोह एक माह पूर्व आई थी और यही रह रही थी। 6 अगस्त की सुबह उसका पति नकुल सिंह ग्राम करीं घर आया और पत्नी को अपने

साथ घर चलने को बोला, जिसपर वह जाने से मना कर दी। जिसके बाद नकुल सिंह क्रोधित होकर पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर ब्लेड से उसके गर्दन में प्राण घातक हमला कर सामने तरफ गला काट दिया। जिससे वह रक्तरंजित हो कर अचेत हो गई जिसे ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस से ओड़गी अस्पताल लाया गया। जहाँ डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार पश्चात गम्भीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल सूरजपुर रेफर कर दिया गया। जिसकी रिपोर्ट पर चौकी कुदरगढ़ में आरोपी के विरूद्ध धारा 109(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

51 अवैध इमारतों का निरीक्षण करेगी टीम

भू उपयोग के उल्लघंन पर कोर्ट ने एलडीए से जतायी नाराजगी

विशेष संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के अलीगंज क्षेत्र में आवासीय भूखंडों पर निर्मित 51 अवैध व्यावसायिक इमारतों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहुंच गया है। न्यायालय की ओर से गठित टीम अगले दो सप्ताह के भीतर लखनऊ पहुंचकर इन भवनों का भौतिक सत्यापन और स्थलीय निरीक्षण करेगी। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि भवनों की पहचान सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर की गई है, इसलिए अब आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही होगी। यदि सुप्रीम कोर्ट ध्वस्तीकरण या अन्य कार्रवाई का आदेश देता है तो एलडीए उसका अनुपालन करेगा। वहीं, यदि न्यायालय किसी प्रकार की राहत देता है तो संबंधित भवन स्वामियों को उसका

पूरे देश में लैंड यूज उल्लंघन पर नजर : सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 25 मार्च 2026 के आदेश के जरिए मामले का दायरा बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया था। अदालत का कहना है कि राजधानी शहरों और बड़े शहरी क्षेत्रों में मास्टर प्लान, भवन उपविधियों और सार्वजनिक सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना राष्ट्रीय महत्व का विषय है। अब अगली सुनवाई में उपाध्यक्ष को रिपोर्ट के साथ अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद अवैध निर्माण और शहरी नियोजन में अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर देशभर में बड़ा संदेश माना जा रहा है।

लाभ मिलेगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, चिन्हित 51 भवन किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अलीगंज के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में स्थित हैं। इन भूखंडों का मूल आवंटन आवासीय उपयोग के लिए किया गया था, लेकिन उन पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और प्रतिष्ठान विकसित किए जाने की शिकायतें हैं। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की निरीक्षण टीम की रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि उसी के आधार पर इन भवनों के भविष्य और संभावित कार्रवाई का फैसला होगा। उधर, भीषण अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में सीलबंद लिफाफे में विशेष जांच दल की रिपोर्ट लेकर उपस्थित हों। अदालत ने यह भी पूछा है कि न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने के मामले में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ कर रही है। सुनवाई के दौरान न्यायालय के एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने अदालत को बताया कि जिस भवन में आग लगी थी, उसे ध्वस्त करने का आदेश पहले ही 10 मई 2016 को जारी किया गया था।

उन्होंने बताया कि इसके बावजूद 5 जुलाई 2016 को तकनीकी आधार का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने अपना ही आदेश वापस ले लिया। इसके बाद कई वर्षों तक भवन के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और अंततः जून 2026 में हुए अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत हो गई।

लैब में तैयार सेल्स से पेशाब की नली की बीमारी के इलाज में सफलता

लखनऊ। प्रदेश में पहली बार लैब में तैयार की गई सेल्स की मदद से यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर यानी पेशाब की नली के सिकुड़ने की बीमारी का सफल इलाज किया गया है। यह कारनामा अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की टीम ने किया है। डॉ. मयंक अग्रवाल, डॉ. वेद भास्कर और डॉ. शैलेंद्र गुप्ता की टीम ने 30 वर्षीय लखनऊ निवासी मरीज का ऑपरेशन किया। मरीज 3 सेमी लंबी बुलबर यूरिथ्रा स्ट्रिक्चर से पीड़ित था। डाक्टरों ने मरीज के गाल के अंदर से सिर्फ 10 एमएम गुणा 5 एमएम का छोटा सा ऊतक लिया। इसे हवाई मार्ग से पुणे की लैब भेजा गया। वहां 2 हफ्ते में टिश्यू इंजीनियरिंग से करीब 50 लाख सेल्स तैयार किए गए। इन सेल्स की लाइफ सिर्फ 72 घंटे होती है, इसलिए कोल्ड चेन में रखकर वापस लखनऊ लाया गया। अगले दिन दूरबीन की मदद से इन सेल्स को लिक्विड थ्रोम्बिन के साथ मिलाकर नली के सिकुड़े हिस्से पर लगाया गया। पूरी प्रक्रिया सिर्फ 15-20 मिनट में पूरी हुई।

आगरा एक्सप्रेस-वे पर एलडीए लायेगा वशिष्ठ नगर योजना

स्टेट कैपिटल रीजन का ग्रोथ इंजन बनेगी 1035 एकड़ की यह योजना

विशेष संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण आगरा एक्सप्रेस-वे पर लगभग 1035 एकड़ क्षेत्रफल में वशिष्ठ नगर योजना विकसित करेगा। यह योजना न सिर्फ उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स व आर्थिक गतिविधियों को गति देगी, बल्कि राजधानी को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन से जोड़ेगी।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इसे मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। वशिष्ठ नगर योजना में विश्वस्तरीय औद्योगिक अवसंरचना विकसित होने से बाहरी निवेश आकर्षित होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने

बताया कि स्टेट कैपिटल रीजन के विजन को साकार करने के लिए जरूरी है कि क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किये जाएं। इसके लिए औद्योगिक विकास, निर्बाध कनेक्टिविटी, सतत विकास तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वशिष्ठ नगर योजना की रूपरेखा तैयार की गयी है। जिसमें आधुनिक औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स हब, उत्कृष्ट रोड नेटवर्क, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना तथा पर्यावरणीय संतुलन पर विशेष बल दिया गया है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि वशिष्ठ नगर योजना आगरा एक्सप्रेस-वे, मोहन रोड, लिंक एक्सप्रेस-वे तथा वरुण विहार योजना जैसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर से सीधे कनेक्ट होगी। इससे उद्योग, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना में अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल भी विकसित किया जाएगा।

इन गांवों की जमीन चिन्हित

उपाध्यक्ष ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे के एक तरफ वरूण विहार योजना और दूसरी तरफ वशिष्ठ नगर योजना विकसित की जाएगी। वशिष्ठ नगर के लिए ग्राम-रेवरी, भलिया, गहलवारा, आदमपुर इन्दवारा, बहरू एवं जलियामऊ की लगभग 1035 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है। शासन से मंजूरी मिलते ही किसानों से सहमति व अन्य माध्यमों के आधार पर योजना के लिए भूमि जुटाव का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भूमि संकलित करने में लगभग 1328 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे।

विकसित भारत जी-राम-जी योजना से बदली तस्वीर, रोजगार और सिंचाई दोनों को मिला संबल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कालामांजन में विकसित भारत जी-राम-जी योजना के तहत निर्मित मिट्टी बांध आज ग्रामीणों के लिए आजीविका और कृषि विकास का सशक्त माध्यम बन गया है। इस बांध ने न केवल सिंचाई की सुविधा को मजबूत किया है, बल्कि ग्रामीणों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

गाँव के किसान श्री सुखनंदन सिंह इस परिवर्तन की प्रेरणादायक मिसाल हैं। पहले वे मुख्य रूप से धान की खेती पर निर्भर थे, लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था। मिट्टी बांध के निर्माण के बाद उन्होंने मछली पालन शुरू किया, जिससे आज वे प्रतिवर्ष लगभग 50 हजार से 01 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर रहे हैं। शासन की ओर से उन्हें वर्ष में दो किश्तों में तीन-तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता के साथ मछली बीज, जाल इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनका व्यवसाय और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

श्री सुखनंदन सिंह बताते हैं कि मछली पालन से होने वाली अतिरिक्त आय का उपयोग वे अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा तथा खेती के लिए खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में करते हैं। वे इस पहल के लिए छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मिट्टी बांध का लाभ केवल एक किसान तक सीमित नहीं है। आसपास के अनेक किसान भी इस जलस्रोत का उपयोग धान सहित अन्य फसलों की सिंचाई के लिए कर रहे हैं, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक हेतु 10 को देवगढ़ धाम रवाना होंगे कांवरिये

कांवर पदयात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सरगुजा अंचल की आस्था का प्रमुख केंद्र और जमदगिनी ऋषि की तपोभूमि व उत्तर प्रवाहित पावन सलिला रेणुका नदी के तट स्थित

अर्धनारेश्वर प्राचीन शिवलिंग देवगढ़ धाम में आगामी 10 अगस्त को आयोजित होने वाली कांवर पदयात्रा एवं भव्य भजन संध्या को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस वर्ष भी माँ कुदरगढ़ी सेवा परिवार, सूरजपुर के तत्वावधान में आयोजित होने वाले 11 वें वार्षिक उत्सव एक शाम देवगढ़ बाबा के नाम की भजन संध्या व सजीव झांकियों के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। आयोजकों के अनुसार परंपरानुसार बड़ी संख्या में शिवभक्त गायत्री मंदिर छठ घाट से पवित्र कांवर व जल लेकर बोल बम के जयघोष के साथ देवगढ़ धाम के लिए पदयात्रा करेंगे। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे इस कांवर यात्रा में शामिल होकर भक्ति गीतों और हर-हर महादेव के उद्घोष के साथ झूमते-गाते देवगढ़ धाम पहुंचते हैं। पूरी यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम बन जाती है।

आस्था की इस परंपरा के तहत महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व कांवर उठाई जाती है। जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बन जाता है। पदयात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह जलपान, भोजन और विश्राम की व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसके साथ ही मेडिकल सेवा भी उपलब्ध रहेगी, ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कार्यक्रम के अंतर्गत 10 अगस्त की रात्रि 7.30 बजे से बाबा की इच्छा तक भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा। इसमें प्रसिद्ध भजन प्रवक्ता अंजली गुप्ता मध्यप्रदेश, शुभम भास्कर कोलकाता, सरगम स्नेहा देवघर बाबा धाम और शुभम गुप्ता मध्यप्रदेश अपनी मधुर प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर करेंगे।

माँ कुदरगढ़ी सेवा परिवार ने क्षेत्रवासियों एवं शिवभक्तों से अधिक से अधिक संख्या में कांवर पदयात्रा एवं भजन संध्या में शामिल होकर देवगढ़ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। इस दौरान छट घाट में अनूप अग्रवाल, अरुण गुप्ता, बसन्त मिश्रा, महामाया चौक में पन्नू साहू, लांची में लालचंद अग्रवाल, पासिंग नाला में नव युवा जागृति मंच, केतका रोड में सवारियां सेठ समिति, केतका में बैजनाथ अग्रवाल, महंगई में विजय कुमार विष्णु राम, बड़पारा नलिन जिंदल व देवगढ़ धाम में राहुल अग्रवाल व टीम के साथ रात्रि में माँ कुदरगढ़ सेवा परिवार एवं दूसरे दिन विनोद कुमार विकास कुमार अम्बिकापुर के साथ पानी की विशेष व्यवस्था रौनक जैन व अन्य विभिन्न समाज सेवियो व संस्थाओं के द्वारा व्यवस्थाएं निःशुल्क की गई है। आयोजन को सफल बनाने में पवन गर्ग, सुभाष गोयल, कालीचरण अग्रवाल, राजेश मित्तल, पवन अग्रवाल, चिंटू अग्रवाल, पंकज चौबे, गोलू जिंदिया, नवीन सिंघल, मुकेश अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, बंटी जिन्दीया, घनश्याम गोयल, विकास जैन, राजेश डालमिया, नलिन जिंदल, रूपेश मित्तल, प्रणव अग्रवाल सहित समिति के सदस्य सक्रिय हैं।

एल्कोमीटर से पुलिस ने की वाहन चालकों की जांच, नशे में पाए गए 3 चालक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 6 अगस्त को जिले के थाना-चौकी की पुलिस द्वारा एनएच-43 सहित अन्य मार्गो पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान 03 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते मिले जिनके विरूद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एनएच-43 सहित कई मार्गो से गुजरने वाले दोपहिया एवं चारपहिया वाहन चालकों की एल्कोमीटर के माध्यम से जांच की। पुलिस ने वाहन चालकों को रोककर उनका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया तथा यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में आवश्यक समझाइश भी दी। जांच के दौरान 03 वाहन चालक शराब के नशे में पाए गए जिनके विरूद्ध धारा 185 एमव्ही एक्ट के तहत कार्यवाही कर इस्तगाशा न्यायालय में पेश किया जाएगा।

अभियान के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को बताया कि शराब के नशे में वाहन चलाना स्वयं के साथ-साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है। थोड़ी-सी लापरवाही भी बड़ी सड़क दुर्घटना का कारण बन सकती है। सभी वाहन चालकों से वाहन चलाते समय निर्धारित गति सीमा का पालन करने, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने निर्देश दिए हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जिलेभर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध नियमित रूप से सघन जांच अभियान जारी रहेगा। भविष्य में शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

विश्व आदिवासी दिवस पर कल भैयाथान से सूरजपुर तक गूंजेगा एकता का स्वर

निकलेगी भव्य बाइक व कार रैली, पारंपरिक संस्कृति की दिखेगी झलक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की तैयारियां जिले के भैयाथान एवं ओड़गी विकासखंड के पंचायतों में अंतिम चरण में पहुंच गई हैं।

ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों में कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। गांव-गांव में बैठकों, जनसंपर्क एवं रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आयोजन समिति के अनुसार बिहारपुर, ओड़गी एवं बैजनाथपुर, भैंसामुंडा, पकनी, दवना, मोहली सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग बाइक एवं कार रैली के साथ भैयाथान पहुंचेंगे। रैलियां भैयाथान में एकत्रित होने के बाद जिला मुख्यालय के लिए रवाना होगा। रैली के दौरान प्रतिभागी पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा, लोक संस्कृति, पारंपरिक वाद्ययंत्र एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेंगे। पूरे मार्ग में क्रांतिकारी महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं वीर शहीदों के जयघोष के साथ जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जल-जंगल-जमीन हमारी पहचान जैसे नारों से वातावरण गुंजायमान रहेगा।

आयोजन समिति ने बताया कि यह आयोजन समाज की एकता, संस्कृति, परंपरा, स्वाभिमान और महापुरुषों के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास है। सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों, युवाओं, महिलाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की अपील की गई है।

संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखने कोटवारों को निर्देश

झिलमिली थाना प्रभारी ने ली कोटवारों की बैठक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। एसपी योगेश पटेल के निर्देश पर जिले में ग्राम स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा सूचना तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से गुरुवार को झिलमिली में थाना प्रभारी सरफराज फिरदौसी द्वारा क्षेत्र के कोटवारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना प्रभारी ने सभी कोटवारों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक माह कम से कम दो बार थाना में उपस्थित होकर अपने-अपने गांव की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था तथा गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराएं। गांव में आने वाले अजनबी एवं संदिग्ध व्यक्तियों, अवैध प्रवासियों, किरायेदारों तथा मुसाफिरों का सत्यापन कर उनका नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एवं फोटो रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए।थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, बाहरी व्यक्ति की असामान्य आवाजाही, झगड़ा-विवाद, अवैध शराब बिक्री, जुआ-सट्टा, मादक पदार्थों के कारोबार, पशु तस्करी, चोरी अथवा अन्य अपराध संबंधी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। प्रभारी ने कोटवारों को कहा कि गांव में नए किरायेदार आने पर तत्काल उनका सत्यापन कराए, रात के वक्त गांव में घूमने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखें। गांव के सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, पंचायत भवन एवं बाजार क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। साइबर ठगी, बैंक फ्रॉड एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करें। महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दें। किसी भी अफवाह, भड़काऊ संदेश या सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी की पुष्टि किए बिना उसे प्रसारित न हो उसके लिए जागरूकता फैलाए। ग्राम स्तर पर शांति समिति एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए। बैठक के दौरान सभी कोटवारों को सत्यापन कार्य सुचारु रूप से करने हेतु रजिस्टर एवं पेन वितरित किए गए। थाना प्रभारी ने बताया कि ग्राम कोटवार पुलिस की आंख और कान होते हैं तथा उनकी सक्रियता से अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मिलेगा। सूरजपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे गांव में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि अथवा अवैध कार्य की जानकारी तत्काल निकटतम थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष को दें तथा सुरक्षित एवं अपराधमुक्त समाज के निर्माण में पुलिस का सहयोग करें।

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर जिला–सरगुजा
रा०प्र०क्र० / अ–6 / 2025–26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण रामकली देवी बेवा स्व. रामनरेश गिरी, अजय कुमार गिरी, विजय गिरी, संजय गिरी आ.स्व. रामनरेश गिरी, सभी जाति गोस्वामी निवासी डी०सी० रोड़ अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदकगण के पति / पिता रामनरेश गिरी आ. स्व. राधा गिरी के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ०पुर, मोहल्ला डी०सी० रोड़ स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 1316 / 2 रकबा 0.00¾ एकड़ भूमि है। भूधारक रामनरेश गिरी की मृत्यु दिनांक 18.08.2017 को हो गई है तत्पश्चात आवेदकगण द्वारा आवेदित भूमि से मृत्तक रामनरेश गिरी का नाम विलोपित करते हुये स्वयं के नाम से फौती नामांतरण किये जाने हेतु मृत्तक रामनरेश गिरी के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 24 / 08 / 2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 07 / 08 / 2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना करें सुनिश्चित : निषाद

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने ली विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद ने सूरजपुर प्रवास के दौरान जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चंद्रकांती वर्मा, आयोग के सचिव संकल्प साहू तथा विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष श्री निषाद ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योजनाओं का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को केवल आंकड़ों तक सीमित न रहकर योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उपाध्यक्ष श्रीमती चंद्रकांती वर्मा ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की वास्तविक प्रगति का नियमित फील्ड निरीक्षण कर प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में सर्वप्रथम जिले का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को जारी एवं निरस्त जाति प्रमाण-पत्रों, विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, समाज कल्याण विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, श्रम,

क्रेडा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कौशल विकास प्राधिकरण, खाद्य, शिक्षा, आदिवासी विकास तथा राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष ने जिले में बागवानी फसलों का रकबा बढ़ाने, किसानों को उद्यानिकी के प्रति प्रोत्साहित करने तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने अदरक एवं हल्दी उत्पादन, किसानी को तकनीकी प्रशिक्षण, बीज उत्पादन, माली प्रशिक्षण तथा किसानों के अध्ययन भ्रमण की जानकारी प्राप्त की। साथ ही लाभान्वित किसानों के निरंतर संपर्क में रहकर उनके जीवन स्तर में आए सुधार की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। पशुधन विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने, प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों को सक्रिय बनाने तथा उन्हें अनुदान एवं अन्य योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा में जिले के कुल जल क्षेत्र, मत्स्य पालन क्षेत्र, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य सहकारी समितियों तथा केनापारा में संचालित केज कल्चर की जानकारी ली। उन्होंने अधिकाधिक पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार वितरण, गर्म भोजन, नोनी सुरक्षा योजना, बच्चों की उपस्थिति, भवनों की स्थिति, स्वयं सहायता समूहों द्वारा पोषण आहार उत्पादन, एनआरसी में कुपोषित बच्चों के उपचार तथा सीडीपीओ एवं सुपरवाइजरों के नियमित फील्ड निरीक्षण की समीक्षा की।

उन्होंने गंभीर कुपोषित बच्चों के समुचित उपचार एवं सुपोषण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लाभान्वित होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की।कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान सरसों, सूरजमुखी एवं मूंगफली जैसी तिलहनी फसलों के उत्पादन, मधुमक्खी पालन, किसान संगोष्ठियों, फसल चक्र परिवर्तन, आत्मा योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, मृदा परीक्षण तथा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्सऑयलसीड्स के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए लगातार जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही फसल बीमा योजना सहित सभी अन्य योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हितग्राहियों और उनकी स्थिति की जानकारी ली। श्रम विभाग के अंतर्गत मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, नौनी-बाबू छात्रवृत्ति सहायता योजना, निःशुल्क कोचिंग सहायता तथा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों श्रम विभाग से मिल रहे लाभ की जानकारी ली और ज्यादा से ज्यादा लोगों का श्रम पंजीयन करने के निर्देश दिए। क्रेडा विभाग की समीक्षा के दौरान स्थापित सोलर पैनलों, सौर सुजला योजना तथा सोलर संयंत्रों के रखरखाव एवं मरम्मत की जानकारी ली गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों एवं पेयजल उपलब्धता की समीक्षा की गई। उन्होंने जिले में पेयजल प्रदाय की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण उपरांत उपलब्ध रोजगार की जानकारी ली गई। उन्होंने सभी प्रशिक्षित लोगों को रोजगार शत प्रतिशत उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने को कहा। शिक्षा विभाग की समीक्षा में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, निःशुल्क गणवेश वितरण, सरस्वती साइकिल योजना, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों सहित अन्य सभी योजनाओं की की प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही जिले में छात्रावासों और छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी ली।

आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान छात्रावासों एवं आश्रमों में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली गई। बैठक में सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए जिले की सहकारी समितियों को अधिक सक्रिय एवं सशक्त बनाने तथा उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़कर प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खाद्य, व्यापार एवं उद्योगऔर स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की योजनाओं की भी विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कोरिया फ्रंटलाइन

अच्छा और बड़ा सोचो, लक्ष्य हासिल करने के लिए जुनून जरूरी: कलेक्टर

कला, कौशल और तकनीक के समन्वय से विद्यार्थियों का भविष्य होगा उज्ज्वल

■ छात्राओं के साथ सीखी वुडन-बंबू आर्ट, एआर-वीआर आधारित डिजिटल शिक्षा का ले रहें अनुभव

छ.ग.फ्रंटलाइन

बैकुंठपुर। कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए बड़ा सपना देखना और उसे पूरा करने का जुनून होना सबसे जरूरी है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि लक्ष्य तय करें, नियमित अध्ययन करें और अपने शिक्षकों से निरंतर मार्गदर्शन लेते रहें। मेहनत और लगन से हर मंजिल हासिल की जा सकती है।

शुक्रवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पटना में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), सेवा केंद्र नया रायपुर द्वारा आयोजित प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंची कलेक्टर ने छात्राओं से आत्मीय संवाद किया तथा उनके द्वारा तैयार हस्तशिल्प उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने बांस शिल्प, वुडन आर्ट, पैरा आर्ट एवं पारंपरिक गोदना पेंटिंग की सराहना करते हुए कहा कि हर बच्चे में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। जरूरत केवल उसे पहचानने, निखारने और उचित मंच उपलब्ध कराने की है। कलेक्टर ने बारहवीं की छात्राओं से उनके भविष्य के लक्ष्य पूछे। छात्राओं ने डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पुलिस अधिकारी और वकील बनने की इच्छा जताई। इस पर उन्होंने कहा कि केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके अनुरूप अभी से तैयारी करना भी आवश्यक है। उन्होंने प्राचार्य को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की रुचि और क्षमता के अनुसार समय-समय पर उनका मार्गदर्शन एवं काउंसिलिंग सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने छात्राओं से नृत्य एवं संगीत में रुचि के बारे में भी चर्चा की। कक्षा सातवीं की छात्रा कुमारी दीपिका सोनवानी ने मधुर गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। छात्राओं ने कलेक्टर का आकर्षक चित्र भेंट किया। सरगुजा की प्रसिद्ध गोदना पेंटिंग कलाकार श्रीमती सफायन पावले ने कोसा शॉल पर निर्मित पारंपरिक गोदना कला की उत्कृष्ट कृति भेंट की, जबकि जशपुर के शिल्पकारों ने बांस एवं छीन से निर्मित हस्तशिल्प सामग्री भेंट की। जशपुर और सरगुजा से आए कारीगरों ने छात्राओं को वुडन आर्ट एवं बंबू आर्ट की तकनीक, निर्माण प्रक्रिया और शिल्प की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया। कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने वुडन-बंबू आर्ट सीखने वाले छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। छात्राओं ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उन्हें पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ स्वरोजगार की नई संभावनाओं की जानकारी मिली है। कलेक्टर ने विद्यालय में संचालित 'मिशन कामयाबी' के अंतर्गत विकसित डिजिटल लर्निंग लैब का अवलोकन किया तथा एआर (ऑगमेंटेड रियलिटी), वी आर (वर्चुअल रियलिटी), एक्सपीरिएंशियल लर्निंग और आधुनिक शिक्षण तकनीकों का स्वयं अनुभव किया।

उन्होंने कहा कि अब शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहेगी। आधुनिक तकनीक के माध्यम से विद्यार्थी विज्ञान, गणित, इतिहास एवं अन्य विषयों को देखकर, समझकर और स्वयं करके सीख सकेंगे। इससे विद्यार्थियों में रचनात्मकता, नवाचार, समस्या-समाधान क्षमता तथा 21वीं सदी के आवश्यक कौशल विकसित होंगे। कलेक्टर ने प्रशिक्षण दे रहे शिक्षक से कहा बहुत ही गम्भीरता से इस पर ध्यान दें ताकि हमारे बच्चे इन विषयों पर ज्यादा रूचि लेकर आगे बढ़ें। कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कहा कि पारंपरिक कला, आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समन्वय विद्यार्थियों को आत्मविश्वासी, रोजगारोन्मुख और आत्मनिर्भर बनाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में ऐसे नवाचार बच्चों के सपनों को नई उड़ान देंगे और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। इसके पहले छात्राओं ने कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव का टीका लगाकर स्वागत किया तथा स्कूल परिसर में श्रीमती यादव ने सीता फल का पौधरोपण किया और बच्चों से कहा जब अवसर मिले तब पौधरोपण जरूर करें और उनकी देखभाल बच्चों की तरह ही करें।

सिटी कोतवाली पुलिस मनेन्द्रगढ़ की अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई

छ.ग.फ्रंटलाइन

मनेन्द्रगढ़ (एमसीबी)। कोतवाली पुलिस ने बिना नम्बर की स्कूटी में 105 पाव अंग्रेजी शराब का परिवहन करते एक युवक को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर जेल की राह दिखा दी है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह (आईपीएस) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा के मार्गदर्शन और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले के सटीक सूचना तंत्र में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिना पंजीयन नंबर की टीवीएस जुपिटर स्कूटी से एक युवक चनवारीडांड की ओर से मनेन्द्रगढ़ की तरफ अवैध अंग्रेजी शराब लेकर आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने फॉरेस्ट डिपो के आगे मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर संदिग्ध स्कूटी को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान स्कूटी के सामने रखे प्लास्टिक के बैग से रॉयल स्टैग अंग्रेजी शराब की 28 पाव (180 मिली) तथा मैकडॉवेल्स नंबर-1 की 77 पाव (180 मिली) कुल 105 पाव अंग्रेजी शराब बरामद हुई। जब्त शराब की कुल मात्रा 18.900 लीटर तथा अनुमानित कीमत 22,680 रुपये आंकी गई। पुलिस ने शराब परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबर की टीवीएस जुपिटर स्कूटी भी जब्त कर ली जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपये बताई गई है। इस प्रकार मामले में कुल 92,680 रुपये का मशरूका जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महेंद्र सिंह धुर्वे (22 वर्ष) निवासी ग्राम मेढ़ाखार करपा थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर (मध्यप्रदेश) हाल मुकाम चनवारीडाँड़ तालाब के पास के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले, उपनिरीक्षक जयालक्ष्मी, सहायक उपनिरीक्षक चेतन राजवाड़े, प्रधान आरक्षक जय यादव, आरक्षक दीप नारायण तिवारी (सायबर सेल) सहित सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ की पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

नेशनल लोक अदालत एवं मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 3.0 अभियान की सफलता हेतु न्यायाधीशों की समीक्षा बैठक आयोजित

12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की हुई समीक्षा

छ.ग.फ्रंटलाइन

बैकुंठपुर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में संचालित श्मध्यस्थता राष्ट्र के लिएश् 3.0 अभियान तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को सफल बनाने के उद्देश्य से गत गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, बैकुण्ठपुर के सभागार में समीक्षा एवं रणनीति बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुण्ठपुर योगेश पारीक ने की। उन्होंने न्यायालयों में लंबित ऐसे सभी उपयुक्त प्रकरणों का सूक्ष्म परीक्षण कर उन्हें अधिक से अधिक संख्या में मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के निर्देश दिए। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए समझौता योग्य प्रकरणों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को प्री-सिटिंग हेतु नोटिस जारी करने तथा उन्हें लोक अदालत के लाभों से अवगत कराने पर विशेष जोर दिया, ताकि अधिकाधिक मामलों का आपसी सहमति से निराकरण हो सके।

बैठक में न्यायाधीशों ने न्यायिक कार्य के दौरान मध्यस्थता एवं लोक अदालत से संबंधित विभिन्न व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। इसमें पक्षकारों की सहभागिता, अधिवक्ताओं के सहयोग, उपयुक्त प्रकरणों का चयन, समयबद्ध रेफरल प्रक्रिया, समझौते की संभावनाओं का आकलन तथा प्रभावी समन्वय जैसे विषय शामिल रहे। अभियान के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए, जिससे अधिकाधिक प्रकरणों का सफल एवं शीघ्र निराकरण किया जा सके। बैठक में मध्यस्थता केंद्र बैकुण्ठपुर के नोडल अधिकारी एवं न्यायाधीश श्री समीर कुजूर सहित जिला मुख्यालय में पदस्थ सभी न्यायाधीश उपस्थित रहे। वहीं सिविल न्यायालय मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी एवं जनकपुर के न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

शराब के नशे में मिले प्रधान पाठक, तत्काल निलंबित

बैकुंठपुर। शा. प्रा. शाला रजवारीपारा, वि.ख. बैकुंठपुर के प्रधान पाठक राम कुमार राजवाड़े को स्कूल समय में कथित रूप से शराब के नशे में पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बैकुण्ठपुर एवं संकुल प्राचार्य तथा शैक्षिक समन्वयक के निरीक्षण में विद्यालय परिसर और व्यवस्थाओं में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। निरीक्षण के दौरान प्रधान पाठक से बातचीत के समय उनके मुंह से शराब की तीव्र गंध आने तथा उनकी बोली अस्पष्ट होने की बात प्रतिवेदन में दर्ज की गई। 7निरीक्षण में कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव द्वारा शिकायत प्रथम दृष्टया में सही पाई गई। शिक्षक के आचरण एवं पदीय दायित्वों के प्रतिकूल मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

पहली बार नैनो डीएपी अपनाकर वैज्ञानिक खेती की ओर बढ़े किसान राजमन सिंह

छ.ग.फ्रंटलाइन

एमसीबी। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसका सकारात्मक प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के विकासखंड खड़गवां अंतर्गत ग्राम जरौधा के किसान राजमन सिंह ने इस खरीफ सीजन में पहली बार अपनी फसल में नैनो डीएपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। उनका मानना है कि आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाकर कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। राजमन सिंह ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से अपनी आवश्यकता अनुसार नैनो डीएपी प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उनके गांव तथा आसपास के कई किसानों ने नैनो डीएपी का उपयोग किया था, जिसके परिणाम काफी उत्साहजनक रहे। फसलों की अच्छी बढ़वार और बेहतर उत्पादन को देखकर उनके मन में भी इस आधुनिक उर्वरक के प्रति विश्वास बढ़ा और उन्होंने इस वर्ष स्वयं इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। राजमन सिंह ने कहा, मैं पहली बार नैनो डीएपी का उपयोग कर रहा हूं। पिछले साल आसपास के किसानों को इसके अच्छे परिणाम मिले थे। उनकी फसल देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली। मुझे विश्वास है कि इसके उपयोग से मेरी फसल की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

उन्होंने बताया कि नैनो डीएपी का एक बड़ा लाभ इसकी आसान परिवहन व्यवस्था भी है। पहले पारंपरिक उर्वरकों की भारी बोरियां ढोनी पड़ती थीं, जबकि नैनो डीएपी की छोटी बोतल को आसानी से बैग में रखकर घर लाया जा सकता है। इससे समय, श्रम और परिवहन की लागत तीनों में बचत होती है। राजमन सिंह ने अन्य किसानों से भी नई कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यदि वैज्ञानिक सलाह के अनुसार आधुनिक उर्वरकों का सही उपयोग किया जाए तो खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन सकती है। कृषि विभाग द्वारा जिले में किसानों को नैनो डीएपी सहित आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग के संबंध में लगातार मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के मार्गदर्शन में छह गांवों तक पहुंची हस्तशिल्प विकास योजनाएं

■ हस्तशिल्प चौपालों में कारीगरों को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और विपणन की दी गई जानकारी

छ.ग.फ्रंटलाइन

बैकुंठपुर। जिला प्रशासन के सहयोग और कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के मार्गदर्शन में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत हस्तशिल्प सेवा केन्द्र, जगदलपुर द्वारा जिले के छह गांवों में 2 से 7 अगस्त तक हस्तशिल्प चौपालों का आयोजन किया गया। चौपालों के माध्यम से ग्रामीण हस्तशिल्पियों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, कौशल उन्नयन, डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास, विपणन सहायता तथा स्वरोजगार के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी गई।

सहायक निदेशक मनोज राठी के नेतृत्व में आयोजित चौपाल कार्यक्रम सोनहत विकासखंड के चकडांड, आनंदपुर, पोंडीबचरा और सलगवां तथा बैकुंठपुर विकासखंड के सरडी एवं पतरापाली गांवों में आयोजित हुए। इनमें बड़ी संख्या में स्थानीय हस्तशिल्पियों ने भाग लेकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा अपनी समस्याएं और सुझाव भी साझा किए। कार्यक्रमों के सफल संचालन में कलेक्टर रोक्तिमा यादव के मार्गदर्शन से जिला प्रशासन और हस्तशिल्प सेवा केन्द्र, जगदलपुर के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ, जिससे सभी कार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए। सहायक निदेशक मनोज राठी ने कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेन्द्र श्रीवास के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग से भारत सरकार की हस्तशिल्प विकास योजनाओं की जानकारी प्रभावी रूप से ग्रामीण हस्तशिल्पियों तक पहुंची है। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे प्रयास हस्तशिल्पियों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को नई दिशा देंगे। उल्लेखनीय है कि इन चौपाल कार्यक्रमों के माध्यम से जिले के अनेक हस्तशिल्पियों को सरकारी योजनाओं से जुड़ने और स्वरोजगार के नए अवसरों की जानकारी प्राप्त हुई।

15 अगस्त को जिलेभर में आयोजित होगा उल्लास महा-चौपाल

शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को लेकर तैयारियां तेज, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश

छ.ग.फ्रंटलाइन

बैकुंठपुर। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के निर्देशानुसार वर्ष 2026-27 में प्रदेश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिले में 15 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले 'उल्लास महा-चौपाल' कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विगत दिनों बैठक में विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देशन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं उपाध्यक्ष, जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण योगेन्द्र श्रीवास के मार्गदर्शन में आयोजित हुई।

बैठक में बताया गया कि उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का मूल मंत्र श्जन-जन साक्षर, कर्तव्य बोधश् है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के ऐसे वयस्कों को साक्षर बनाना है, जो किसी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साक्षरता को जनभागीदारी से जोड़ते हुए जिलेभर में उल्लास महा-चौपाल का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देशानुसार 15 अगस्त से पूर्व सभी ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों के पारा, मोहल्ला एवं टोला स्तर पर नारा लेखन, फ्लेक्स प्रदर्शित किए जाएंगे तथा कोटवारों के माध्यम से कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही जनप्रतिनिधियों, नवसाक्षरों एवं स्थानीय समुदाय को कार्यक्रम में सहभागिता के लिए आमंत्रित करने तथा मैदानी अमले के सहयोग से जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए उल्लास मोबाइल टॉर्च रैली, मशाल रैली, प्रभात फेरी, साक्षरता ध्वजारोहण, सामूहिक उल्लास शपथ आदि महा-चौपाल एवं कहानियों का कारवां, मातृत्व साक्षरता महासंकल्प, डिजिटल साक्षरता हेल्प डेस्क, सेल्फी प्वाइंट, अंगूठा मुक्त पंचायत, 'अंगूठे से कलम तक' सम्मान समारोह, प्रशस्ति पत्र वितरण, साक्षरता रंगोली, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उल्लास की घंटी, उल्लास दीवार, सुपर-30, ज्ञान रथ, खेलकूद प्रतियोगिताएं सहित विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य

छ.ग.फ्रंटलाइन

बैकुंठपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने के इच्छुक सभी श्रेणी के किसानों के लिए भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है। शासन के निर्देशानुसार जिले में नवीन किसान पंजीयन एवं पंजीयन संबंधी संशोधन की प्रक्रिया 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुका जो 31 अक्टूबर 2026 तक विभागीय वेबसाइट द्धष्ह्य.ष्द्.द्दश1.द्बठ्ठ के ऑनलाइन सोसायटी मॉड्यूल के माध्यम से की जाएगी।

खाद्य अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसान आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए भी पंजीकृत माने जाएंगे। ऐसे किसानों की भूमि, धान का रकबा एवं खसरे का अद्यतन कार्य राजस्व विभाग के माध्यम से एग्रीस्टेक पोर्टल पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वनपट्टाधारी, डूबान क्षेत्र के किसान, शासकीय पट्टेदार, कोटवार, संस्थागत कृषक, अधिया, रेगहा बटाईदार तथा लीज के माध्यम से खेती करने वाले सभी किसानों के लिए भी एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए केवल एग्रीस्टेक पोर्टल पर दर्ज डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान का रकबा ही मान्य होगा। जिन किसानों के पास पूर्व से एग्रीस्टेक फार्मर आईडी एवं किसान कोड उपलब्ध है, उन्हें पुनः नवीन पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि पूर्व से पंजीकृत किसानों द्वारा खरीदी-बिक्री, नामांतरण, बंटवारा, फौती अथवा अन्य माध्यमों से नई भूमि प्राप्त की गई है, तो ऐसी भूमि एवं संबंधित खसरा नंबर का संशोधन धान विक्रय हेतु संबंधित उपार्जन केंद्र अथवा समिति में जाकर ऑनलाइन सोसायटी मॉड्यूल के माध्यम से कराया जा सकता है। खाद्य विभाग ने जिले के सभी पात्र किसानों से निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक पंजीयन एवं संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण कराने की अपील की है, ताकि समर्थन मूल्य पर धान विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

सीएम हेल्पलाइन 1076 के प्रभावी संचालन एवं शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर प्रदेश स्तरीय वर्चुअल प्रशिक्षण सम्पन्न

एमसीबी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के प्रभावी संचालन, शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण तथा पोर्टल के बेहतर उपयोग को लेकर शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय वर्चुअल प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष से विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, विभागीय नोडल अधिकारी तथा शिकायतों के निराकरण से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण में शामिल हुए। प्रशिक्षण का संचालन मास्टर ट्रेनर अंशुल वर्मा, राकेश गोलछा एवं अनुराग दीवान ने किया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के नवीन प्रावधानों, स्तरवार शिकायत निराकरण, समय-सीमा के पालन, विभागीय समन्वय, शिकायत स्थानांतरण, स्पेशल क्लोजर, पोर्टल संचालन तथा गुणवत्तापूर्ण निराकरण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 राज्य शासन की महत्वपूर्ण जन शिकायत निवारण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं सीधे शासन तक पहुंचा सकते हैं। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि शिकायतों का उद्देश्य केवल पोर्टल पर जवाब दर्ज करना नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। इसके लिए आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण, तथ्यात्मक जांच, समाधान के बाद कार्रवाई का विवरण, संबंधित दस्तावेज एवं फोटोग्राफ पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण में शिकायतों के स्तरवार निराकरण की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। बताया गया कि एल-1 स्तर पर विभागीय अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में शिकायत का परीक्षण एवं निराकरण करेंगे। समय पर समाधान नहीं होने अथवा संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में शिकायत क्रमशः एल-2, एल-3 एवं एल-4 स्तर तक पहुंचती है, जहां वरिष्ठ अधिकारी प्रकरण की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेते हैं। अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि यदि कोई शिकायत संबंधित विभाग से जुड़ी नहीं है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व ऑफसेट पुराना पोस्ट ऑफिस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर (छ.ग.) पिन नं. 497001 से मुद्रित व महलपारा बैकुण्ठपुर से प्रकाशित। संपादक- कमलेश शर्मा